

ISSN 2319-8419

Published by



Bi-Annual and Bi-Lingual International Journal

Vol. 14

ISSUE- 20

# GYAN BHAV

Journal of Teacher Education  
(Peer Reviewed)

February  
2025



In Collaboration With  
U.P. Self Finance Colleges' Association

**GYAN BHAV JOURNAL OF TEACHER EDUCATION**  
**EDITOR IN CHIEF**

**Smt. Megha Arora**

Department of Teacher Education  
Gyan Mahavidyalaya, Agra Road,  
Aligarh (U.P)-202002  
Mob. No.- . 9837751300

**ADVISORY COMMITTEE**

**Prof. Harcharan Lal Sharma**

Curriculum Specialist (Moscow)  
(Ex-NCERT, NIOS – GOI)  
Consultant & Co-ordinator,  
School Education Think Tank,  
Surya Foundation, New Delhi  
Mob.No. - 9811687565

**Prof. Gunjan Dubey**

Teacher Education Department  
A.M.U Aligarh  
Mob. No.- 9412459713

**Dr.Jai Prakash Singh**

(Ex. Professor)

Department of Teacher Education  
D.S. (PG) College, Aligarh (U.P.)  
Mob. No.- 9410210482

**Prof. (Dr.) Punita Govil**

Department of Education  
A.M.U. Aligarh  
Mob. No.- 9837146021

**Editorial Board**

**Mr. Girraj Kishore**

Mob. No. 9058382553

**Dr. Ratna Prakash**

Mob.No. 7247875053

**Dr. Beena Agrawal**

Mob.No. 7017568337

**EDITORIAL SECRETARY**

Mr. Jay Prakash Sharma

**Mob.No. 8533803101**

**Gyan Bhav** : Journal of Teacher Education is an Bi Annual and bi-lingual periodical published every year in February and August by Gyan Mahavidyalaya, Aligarh. Department of Teacher Education of Gyan Mahavidyalaya is accredited 'A' Grade with CGPA 3.16 by National Assessment and Accreditation Council (NAAC) on 5<sup>th</sup> July, 2012.

The Journal aims to provide teachers, teacher-educators, educationists, administrators and researchers a forum to present their work to community through original and critical thinking in education.

Manuscripts sent in for publication should be inclusive to Gyan Bhav Journal of Teacher Education. These, along with the abstract, should be in duplicate, typed double-spaced on one side of the sheet only, addressed to the Editor in Chief, Gyan Bhav Journal of Teacher Education, Dept. of Teacher Education, Gyan Mahavidyalaya, Agra Road, Aligarh – 202002

Computer soft copy can be sent by E-mail: [publicationgyan@gmail.com](mailto:publicationgyan@gmail.com)

Copyright of the articles/research papers published in the journal will rest with Gyan Mahavidyalaya and no matter may be reproduced in any form without the prior permission of Gyan Mahavidyalaya. The content of matter are the views of the authors only.

Correspondence related to publication, permission and any other matter should be addressed to the Editor-In-Chief. Our Website: - <http://www.gyanmahavidhyalaya.com/ResearchJournals/GyanBhav>

# CONTENTS

S. No.	TITLE	AUTHOR'S NAME	Page No.
1.	उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मिशन-शक्ति के द्वारा उत्पन्न जागरूकता का अध्ययन	आकांक्षा मिश्रा प्रोफेसर रीना अग्रवाल	1-6
2.	Integrating Life Skills with Curriculum: A Theoretical Approach to Holistic Education	Deepti verma, Dr. Suman Lata Verma	07-12
3.	भारत में शिक्षक-शिक्षा का भविष्य: उभरती कार्य-पद्धतियाँ और प्रतिमान	संजय कुमार प्रजापति डॉ० संदीप कुमार श्रीवास	13-21
4.	AWARENESS ON CYBER SECURITY AMONG PUPIL TEACHERS IN MEERUT DISTRICT	Rashmi Yadav	22-27
5.	Empowering Teachers for Technology Integration: Challenges and Effective Strategies	Sandip Das Dr. Sanjay Singh Yadav	28-34
6.	यू०पी० बोर्ड एवं सी०बी०एस०ई० बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र और छात्राओं की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन	प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा सोनू	35-37
7.	वर्तमान शिक्षा में आदर्शवादी विचारों की प्रासंगिकता	श्रीमती वर्धा शर्मा डॉ० (श्रीमती) बीना अग्रवाल	38-45
8.	Empowering Prospective Teachers through Government Digital Portals: Strategies for Integration in Teacher Education	Subhadra Singh Dr. Surya Narayan Gupta	46-55
9.	Transforming Assessment Approaches in Higher Education as per Vision-2047: Implications of PARAKH	Dr. Jitendra Singh Goyal Jaydev Singh	56-63
10.	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक) की मूल्यांकन प्रक्रिया : उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा	सौरभ कुमार' प्रगति अग्रवाल''	64-76

## उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मिशन-शक्ति के द्वारा उत्पन्न जागरूकता का अध्ययन

\*आकांक्षा मिश्रा  
\*\*प्रोफेसर रीना अग्रवाल

### शोध सार

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम मिशन शक्ति सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को लैंगिक समानता, सुरक्षा और सशक्तीकरण के बारे में शिक्षित करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है। यह शोध पत्र मिशन शक्ति कार्यक्रम के उद्देश्य तथा लक्ष्यों के बारे में छात्र-छात्राओं के मध्य जागरूकता स्तर, उनके दृष्टिकोण व व्यवहार की जाँच करता है। उत्तर-प्रदेश के सीतापुर जनपद के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं से वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि से प्राप्त प्रदत्तों के मात्रात्मक विश्लेषण के माध्यम से, यह शोध मिशन-शक्ति कार्यक्रम की प्रभावशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह शोध 0.05 सार्थकता स्तर पर प्रस्तुत शोध की सार्थकता की जाँच करता है और इस कार्यक्रम के व्यापक प्रभाव व प्रसार को सुनिश्चित करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है।

**मुख्य शब्द-** मिशन-शक्ति, जागरूकता, छात्र-छात्राएँ, उत्तर-प्रदेश, सीतापुर जनपद, उच्च शिक्षण संस्थाएँ

**प्रस्तावना-** उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए सन् 2020 में 'मिशन शक्ति' अभियान का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम का संचालन 4 चरणों में किया गया। पहला चरण शारदीय नवरात्रि की शुभ तिथियों में दिनांक 17-10-2020 से 27-10-2020 तक चला। तदुपरांत वासंतिक नवरात्रि में 26-02-2021 से 21-04-2021 तक दूसरे चरण का संचालन किया गया। तृतीय चरण दिनांक 21-08-2021 से 31-12-2021 तक और अंतिम चरण का शुभारम्भ 14-04-2022 से करते हुए 31-08-2022 तक संचालित हुआ।<sup>(1)</sup>

योगी आदित्यनाथ (मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश) के अनुसार,

“महिला सुरक्षा, गरिमा और सशक्तीकरण को जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है। 'मिशन शक्ति' इसका आधार बनेगा। सशक्त स्त्री, समृद्ध समाज का आधार है।”

मिशन-शक्ति कार्यक्रम उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण पहल है, इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में विभिन्न गतिविधि, कार्यशाला और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है।

अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। पहले चरण को लागू करते समय इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया था, जो कि मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन शक्ति था।

\*छात्रा (एम.एड.), शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, ई0मेल:-  
mishraakanksha069@gmail.com मो0नं0- 9696802286

\*\*प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, ई0मेल:-  
agrawalreena761@gmail.com मो0नं0- 9415300615

- मिशन शक्ति अभियान का प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करना था।
- ऑपरेशन शक्ति का प्रमुख लक्ष्य उन लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करना है, जिन्होंने महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार या अपराध किया है।

मिशन-शक्ति अभियान के दूसरे चरण का कार्यक्रम 5 मुख्य बिंदुओं पर आधारित था। ये 5 मुख्य बिंदु बाल एवं महिला अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक परामर्श, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी और बलपूर्वक भिक्षावृत्ति व बालश्रम पर आधारित थे<sup>2</sup>। मिशन शक्ति 3.0 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत की। इसके अलावा 51 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कक्ष बनाये गये तथा 84.71 करोड़ रुपये की लागत के 1286 थानों में पिंग शौचालय का निर्माण भी किया गया। महिलाओं में रोजगार को बढ़ाने के लिए महिला बटालियन के लिए 2982 पदों पर विशेष भर्ती की गयी। मिशन शक्ति अभियान के दौरान आपातकालीन सेवा 112 यूपी एक मिशन की तरह महिलाओं में शक्ति का अहसास बढ़ा रहा है। खासतौर से विमेन पावर लाइन 1090 व 181 सेवा के 112 यूपी में एकीकरण के बाद महिलाओं को एक ही छत के नीचे सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन से जुड़ी सेवायें एक साथ मिल रही हैं।(3) मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण के अंतर्गत भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किये गये। जैसे- डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बालिका सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा ऐसी महिलाएँ जो इस समाज के लिए आदर्श हैं, उनके साथ प्रेरणास्पद संवाद किये गये। इस चरण में बालिकाओं की शिक्षा और कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को भी शामिल किया गया। इसमें समग्र महिला कल्याण के अन्य पहलुओं को कवर करते हुए पिछले तीन चरणों के पहलुओं में मौजूद प्रावधानों पर काम किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग था- कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को दिलाई जाने वाली शपथ। इसमें दो तरह की शपथ होती थीं- एक विद्यार्थियों द्वारा और एक अभिभावकों द्वारा।(4)

## मिशन शक्ति के लक्ष्य -

### 1. समृद्धि का सामाजिक और आर्थिक समर्थन -

मिशन शक्ति का पहला लक्ष्य यह है कि महिलाएँ समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकें और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त हों। इसके लिए राज्य सरकार ने सामाजिक और आर्थिक समर्थन के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई हैं, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हैं।

### 2. न्यूनतम शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना -

मिशन शक्ति का यह उद्देश्य है कि हर महिला को न्यूनतम शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत की है और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं।

### 3. महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में समाज को जागरूक करना-

इस लक्ष्य के लिए मिशन शक्ति के तहत विभिन्न समागम और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए हैं। इसके माध्यम से समाज को महिलाओं के योगदान को समझने और समर्थित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

प्रस्तुत शोध की आवश्यकता उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रम मिशन-शक्ति की सफलता को जानने के लिए किए गए एक प्रयास के रूप में है तथा इसका औचित्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्थिति को जानने के रूप में है।

### समस्या कथन—

आजादी के बाद महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए लेकिन यह सभी कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाये। अध्ययन यह बताते हैं, कि इन कार्यक्रमों को अर्द्धमन से लागू किया गया तथा लक्ष्य समूह (महिलाओं) में जागरूकता के अभाव और अन्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी कारणों से उनके उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका। उपर्युक्त समस्याओं के आलोक में अब हमें मिशन शक्ति कार्यक्रम को यथार्थ की कसौटी पर कसना है।

### शोध का उद्देश्य—

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की जागरूकता का अध्ययन करना।

### परिकल्पना—

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के प्रति उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जागरूकता में अंतर नहीं है।

### कार्यप्रणाली:

#### शोध विधि—

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

#### शोध की जनसंख्या—

प्रस्तुत शोध पत्र में जनसंख्या के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सीतापुर जनपद के कुल 96 महाविद्यालयों में<sup>(6)</sup> अध्ययनरत स्नातक स्तर के समस्त छात्र-छात्राओं को सम्मिलित किया गया है।

#### शोध का प्रतिदर्श एवं प्रतिदर्श चयन विधि—

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रतिदर्श के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सीतापुर जनपद के कुल महाविद्यालयों में से चयनित तीन महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के कुल 204 विद्यार्थियों को लिया गया है। प्रस्तुतशोध में सर्वप्रथम सीतापुर जनपद में स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 96 महाविद्यालयों में से 3 महाविद्यालयों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक द्वारा किया गया है। तत्पश्चात् चयनित महाविद्यालयों में से स्नातक स्तर के विद्यार्थियों में से 204 छात्र-छात्राओं का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक द्वारा किया गया।

चयनित महाविद्यालयों के नाम

1. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर
2. RMP पी. जी. कॉलेज सीतापुर
3. श्री कृष्णा कॉलेज सीतापुर

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	छात्र	छात्रा	कुल
1	सरकारी महाविद्यालय	34	34	68
2	सहायता-प्राप्त महाविद्यालय	34	34	68
3	निजी महाविद्यालय	34	34	68

शोध उपकरण –

प्रस्तुत शोध में आँकड़ों के संग्रह हेतु शोधार्थी द्वारा निर्मित मापनी का प्रयोग किया गया, जो 5 प्वाइंट लिंकर्ट स्केल पर आधारित है तथा मापनी में कुल कथनों की संख्या 30 है।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या –

प्रस्तुत शोधपत्र में प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकीय टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया। प्राप्त परिणामों का वर्णन इस प्रकार है –

तालिका-1

उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति स्नातक स्तर के विद्यार्थियों की समग्र रूप से जागरूकता –

समूह	विद्यार्थियों की संख्या	माध्य	मानक विचलन	मानक त्रुटि	t-value (calculated value)	t-value (table value)	0.05 स्तर पर सार्थकता
छात्राएँ	102	119.07	8.27	1.342	5.2101	1.98	सार्थक है
छात्र	102	126.06	10.74				

यहाँ प्राप्त छात्राओं का माध्य 119.07 है तथा छात्रों का माध्य 126.06 है तथा मानक त्रुटि 1.342 है और t का मान 5.2101 है, जो 0.05 पर सार्थक है। अतः परिकल्पना उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम के प्रति उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जागरूकता में अंतर नहीं है, अस्वीकृत हो गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के द्वारा उत्पन्न छात्र-छात्राओं की जागरूकता में अंतर है। माध्य के आधार पर ज्ञात होता है कि मिशनशक्ति कार्यक्रम से छात्राओं की तुलना में छात्रों की जागरूकता बढ़ी है।

तालिका-2

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम मिशन शक्ति के विभिन्न आयामों के आधार पर छात्र-छात्राओं की जागरूकता

क्रम संख्य T	मिशन शक्ति के विभिन्न आयामों	समूह	कुल संख्या	माध्य	मानक विचलन	t-Value (calculated value)	t- (table value)	0.05 स्तर पर सार्थकता
1	बाल एवं महिला अधिकार	छात्र	102	418.9	53.79	0.0663	2.45	सार्थक नहीं
		छात्रा	102	417.22	52.82			
2	मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक परामर्श	छात्र	102	404.6	42.41	0.0770	2.45	सार्थक नहीं
		छात्रा	102	402.6	39.69			
3	कन्या भ्रूण हत्या	छात्र	102	425.25	12.20	1.0273	2.45	सार्थक नहीं
		छात्रा	102	416.75	11.80			
4	महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी	छात्र	102	391.6	65.95	0.2859	2.45	सार्थक नहीं
		छात्रा	102	401.00	32.47			
5	बलपूर्वक भिक्षावृत्ति व बालश्रम	छात्र	102	431.67	19.17	0.17668	2.45	सार्थक नहीं
		छात्रा	102	427.67	12.02			
6	विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को शपथ	छात्र	102	425.5	5.97	1.117	2.45	सार्थक नहीं
		छात्रा	102	418.00	12.03			

यहाँ विभिन्न आयामों के आधार पर छात्र-छात्राओं की मिशनशक्ति कार्यक्रम के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया गया जिसमें माध्यों, मानक विचलनों के आधार पर प्राप्त t के मान की 0.05 स्तर पर t के मान से कम हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्र-छात्राओं की जागरूकता में विभिन्न आयामों के आधार पर कोई अंतर नहीं है।

**निष्कर्ष-**

- मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए गए समस्त कार्यक्रमों के अध्ययन के उपरांत प्राप्त परिणामों के आधार पर छात्राओं की तुलना में छात्र ज्यादा जागरूक हुए हैं।
- वहीं विभिन्न आयामों के अध्ययन के उपरांत प्राप्त परिणामों के अनुसार छात्र-छात्राओं की जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।



विवेचना—

विभिन्न आयामों के आधार पर प्राप्त परिणामों में महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी के आयाम को छोड़कर अन्य सभी आयामों में छात्रों का माध्य छात्राओं के माध्य से बहुत कम अंतर से अधिक है इसलिए इन परिणामों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। परन्तु समग्र अध्ययन करने पर एक सार्थक अंतर प्राप्त होता है। इस आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मिशन शक्ति कार्यक्रम का समग्र प्रभाव तथा छात्र-छात्राओं में जागरूकता का स्तर अलग-अलग है तथा उच्च शिक्षा में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं पर उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन-शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से छात्र जागरूक हुए हैं।

संदर्भ ग्रंथ—

1. the print (2020, october 17). योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन की 'मिशन शक्ति' की शुरुआत की. The Print Hindi. <https://hindi.theprint.in/india/uttar-pradesh-cm-yogi-adityanath-launches-mission-shakti-in-balrampur/177628/>
2. योगी आदित्यनाथ (2024, November 8)UP Mission Shakti, <https://upmissionshakti.in/retriverd> 8 november 2024
3. श्री वास्तवस. (2021, August 20). मिशनशक्ति 3.0: नए कलेवर में नजर आएगा मिशनशक्ति का तीसरा चरण, जानेंकिन्हें मिलेगा लाभ? आजतक <https://www.aajtak.in/india/uttar-pradesh/story/mission-shakti-third-cm-yogi-adityanath-women-employment-financia;-help-companies-police-ntc-1313365-2021-08-20>
4. The Hindu Bureau. (2023, October 15). U.P. launches fourth phase of Mission Shakti aimed at empowering women. The Hindu. <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/up-launches-forth-phase-of-mission-shakti-aimed-at-empowering-women/artical67420842.ece>
5. University of Lucknow/ List of associated Colleges.(n.d.). <https://www.lkouniv.ac.in/article/en/collegee-list?cd=MQAyADYAMgA4AA%3D%3D>

## INTEGRATING LIFE SKILLS WITH CURRICULUM: A THEORETICAL APPROACH TO HOLISTIC EDUCATION

*\*Deepti verma,*

*\*\*Dr. Suman Lata Verma*

### ABSTRACT

*The integration of life skills into school curricula is an issue that gains even more importance in light of the rhetoric about holistic education that places more emphasis on the development of the whole person in addition to academic achievements. This paper looks at the theoretical rationales behind and practical applications of mainstreaming life skills such as critical thinking, communication, and emotional regulation across various subject areas. This study ties to the constructivist learning theory; drawing out the experiential learning and social interaction that is perceived to be necessary in developing cognitive as well as emotional competencies. This also brings up the frameworks of Social Emotional Learning in the support of self-awareness, relationship skills, and responsible decision-making. Thus, this paper calls for the adoption of interdisciplinary curriculum designs and teacher training as methods to successfully adopt life skills education into the broader framework of the educational institution towards more engaging students and better performance. As a basic part of new education, despite various obvious merits, there are some difficulties connected with the incorporation of life skills due to insufficient resources and unprepared teachers as well as a curriculum too wide. This paper underlines the need for educators, policymakers, and stakeholders to raise their voices in the call for integration of life skills as the basic human aspect of any new education system. Ultimately, it is teaching them life skills which prepares them not only for academic success but also lays down the essential tools for everyday life, ensuring resilience and adaptability in an ever-changing world.*

**Keywords-** *Life Skills Education , Curriculum Integration , Holistic Education Social-Emotional Learning (SEL), Critical Thinking, 21st-Century Skills, Constructivist Learning.*

### Introduction: -

The ever-changing modern world has played a significant role in shaping education, traditionally depicted through examination results, to prepare students for real-life challenges. Education must change its paradigm with technological advancement and social change that is gathering pace, and the rising need to understand emotional intelligence. Life skills, that is, innovative thinking, problem-solving abilities, emotional regulation, communication, and interpersonal skills are a must for children for dealing with the complexities of modern life. Such competencies should, therefore, be integrated into the curriculum of schools in order to enhance all-round education that emphasizes the wholeness of human development rather than focusing on merely academic performance. Life skills education is very inclusive as it aims at nurturing the cognitive, emotional, and social dimensions of students' development. The World Health Organization defines life skills as abilities that can promote adaptive and healthy behavior to enable people to cope effectively with the demands and challenges of everyday life. This would then mean having life skills embedded in other subject matters making the learning experience more relevant and meaningful to their real lives. Such an approach can thus help the teacher to mold students into individuals who, aside from achieving success academically, also perform well in life.

The theoretical underpinnings for incorporating life skills into the curriculum are taken from diverse frameworks of education. Constructivist learning theories argue that experiences that have their foundations on social relations and self reflections can lead to construction of knowledge. These theories argue that in order for students to develop the critical life skills that would work for them, there should be a case of experiential learning activities involving collaboration and problem-solving. In addition, Socio Emotional Learning frameworks accommodate the requirement of emotional intelligence and self-consciousness in the learning environment. The core competencies already reeled out by WHO are Self awareness, Coping with emotion, Coping with stress Empathy, Effectiveness communication, Interpersonal relationship-Critical Thinking, Creative Thinking, Decision making, Problem solving . The infusion of SEL into the curriculum will seek to create a context through which the student learns to realize and regulate their emotions and extend empathy towards other people and building positive relationships-lifelong. However, a lot of ground has not been covered in implementing these concepts into the curricula despite growing awareness of the role of life skills education. The areas of teacher training, curriculum overloads, and lack of resources are some of the major challenges identified toward the effective implementation of life skills. This paper addresses the theoretical frameworks for the integration of life skills into education and pragmatic strategies for overcoming some of the challenges. It appeals for the holistic approach towards teaching to set students up for lifelong success.

Life Skills given by W.H.O.-

S.N.	Components	Skills
1	Coping and self-management skills	1-Self awareness 2-Coping with emotion 3-Coping with stress
2	Interpersonal/Communication skills:	4-Empathy 5-Effectiveness communication 6-Interpersonal relationship
3	Critical thinking skills and decision-making skills:	7-Critical Thinking 8-Creative Thinking 9-Decision making 10-Problem solving

**Methodology-**

The methodology of this paper is qualitative, resting primarily on a vast review of literature and theoretical analysis. One of the key sources for this paper has been articles from peer-reviewed journals, educational reports, and theoretical texts on life skills education and curriculum integration. The scope of the literature review addressed basic theories of life skill education, such as Social Emotional Learning, constructivism, and experiential learning. In this paper, I discuss how such life skills as critical thinking, communication, and emotional regulation can be inserted into more traditional subjects under academic schooling and assess difficulties and best practices for implementation. This paper synthesizes a holistic framework of integrating life skills into curricula with a purpose for imparting academic success and personal development in students.

**Theoretical Background**

**1. Constructivist Learning Theory-**

Constructivist learning theory focuses primarily on Jean Piaget and Lev Vygotsky, who attribute knowledge construction to learners and explain that they construct knowledge through experiences and social interactions. Piaget's theory explains that the cognitive development is sequential or in

sequences, as the child applies prior knowledge and experiences into newer ones for construction. In this regard, according to Piaget (1952), education should provide scope for exploration and problem-solving that allows students to construct meaning in a nurtured setting. Vygotsky develops this view further when he introduces the Zone of Proximal Development (ZPD), which stresses social roles in cognitive development. When implementing life skills in the curriculum, constructivist tenets support experiential experiences. As students work in groups on projects or activities designed to solve problems, they can practice life skills in naturalistic settings. The extra benefit of this education encourages students to think critically about their learning procedures, creating not only cognition but also emotional and social skill development. Moreover, bringing life skills into the lessons will offer a more holistic learning experience that students can point out and apply toward everyday challenges they might face.

## **2. Framework for Social-Emotional Learning-**

SEL, then, becomes the conceptual base for life skills in teaching. According to Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, SEL is said to have five competencies namely self-awareness, self-management, social awareness, relationship skills, and responsible decision-making. These competencies become essential for developing emotional intelligence and correct socially coherent behavior among the students. Integrating SEL in the curriculum integrates the learning processes in such a way that develops an environment that supports desirable student outcomes. Although numerous studies show the implementations of SEL programs to lead to enhanced academic achievement, better social behaviors, and reduced emotional distress for students (Durlak et al., 2011), embedding SEL principles into the curriculum will allow educators to teach life skills explicitly as well as create natural opportunities for the practice of those skills within authentic contexts. Examples of these life skills include the role-playing activity in the promotion of empathy and suitable communication skills. Thus, by identifying life skills with SEL, there is a support toward the emotional well-being of the students and thereby a ready provision to face the complexities in interpersonal relationships in diverse environments.

## **3. Interdisciplinary Curriculum Design-**

Thus, interdisciplinary curriculum design is a very pragmatic way of integrating life skills across the curriculum, making school experience more fulfilling. An interdisciplinary approach certainly makes it possible for other academic disciplines to combine their efforts, so that students start seeing interconnections between concepts and can find practical ways to put their learning into action. Weaving life skills education across the curriculum-literature, science, social studies-inter connectedly creates a rich learning environment that fosters critical thinking and problem-solving. An example would be to break down how the characters make decisions or do not make decisions within a novel for further characterization skills, which develops empathy and critical thinking. Likewise, group science projects can cultivate teamwork and effective communication. There is evidence that interdisciplinary approaches not only engage learners but also facilitate transfer across context (Wiggins & McTighe, 2005). By embedding life skills into a frame of interdisciplinary learning, it enables teachers to teach students in a more holistic manner to contemporary challenges experienced in the real world. Therefore, they arm them with all the competencies needed to be successful for life.

## **Practical Strategies of Integration**

### **1. Curriculum Mapping-**

Curriculum mapping is a deliberate approach that brings educational content in line with expected learning outcomes. Consequently, there will be intentional incorporation of life skills throughout subjects. Educators can make a curriculum graphic, which could even help identify opportunities to

integrate life skills. These teachers can then brainstorm together and share their best practices and resources as they take up a collaborative approach toward teaching life skills. The process serves not only to define more clearly the place of life skills in the curriculum but also to build better connections across disciplines, so that students understand these skills in the contexts in which they belong.

## **2. Project-Based Learning-**

Project based learning is one of the most effective instructional methods that enable students to engage in real-world problems that make sense through critical thinking, collaboration, and creativity. In fact, when projects are designed with life skills, educators are likely to engage students in authentic learning experiences that invoke active engagement. For example, students may be tasked with coming up with a community service project that activates their communication and teamwork skills as they come together to do something valuable for their community. PBL encourages each learner to be in charge of his or her learning. This way, the students will learn to think deeper and realize not only the content about their school work but also fundamental life skills.

## **3. Professional Development of Teachers-**

The teachers must be well-prepared and given strong professional development training to handle life skill education well. The training programs must be based on pedagogical techniques in teaching life skills. These include active learning strategies and assessment methods. Workshops and collaborative learning communities may provide opportunities to share experiences, resources, and challenges related to life skills education. School leadership, through professional development, can make it a supportive environment in which teachers are enabled to put life skills among their priorities in teaching practice.

## **4. Community Partnerships-**

Good integration can be done by establishing local organizations, businesses, and community members as partners. Schools might engage with community stakeholders and have access to some resources, experience, or real-life expert advice that flavor students' learning. For example, guest speakers from different professions might present their life skills applicability experience practically at the workplace. Community service projects can also give students experiences that serve to reinforce social responsibility and civic engagement. These collaborations form a network of support, reinforcing the importance of life skills for students' lives.

## **5. Continuous Assessment and Feedback-**

Continuous monitoring and feedback are essential for determining if life skills should be incorporated into the curriculum or not. Facilitators must use different methods of assessment such as peer evaluation, self-assessments, and reflective journaling to find out how well students have applied their skills in life. Feedback from students, parents, and teachers will help in knowing which areas really need improvement and in which the current teaching methods are strong in teaching life skills education. And through proper assessment of their student progress, with the revision of proper instructional strategies, educators can ensure that there is infusion of life skills within the learning experience that leads towards the readiness of its recipients for successful performance, both personal and professional, in later life.

## **Challenges in Implementation-**

Even though due importance is given to the integration of life skills into curricula, still several challenges hinder effective implementation. Various challenges have sprung against the proper delivery of life skills by educators and may affect the entire process of learning for a learner.

### **1. Lack of Teacher Training-**

Perhaps the largest impediment to curriculum integration of life skills is that most teachers are not well-rounded. Most instructors state they were not adequately prepared by the professional development experiences to use academic content in teaching life skills. Only well-prepared teachers will be confident and knowledgeable enough to provide life skills consistently and avoid lost opportunities for the students' growth (Rimm-Kaufman & Sandilos, 2012).

### **2. Curriculum Overload-**

Curriculum overload seems to be the result when so much academic content has to fit into such short periods. Ultimately, this will leave no scope for life skills education to be integrated. Educators always fixate on test performances, as well as academics and do not consider life skills to be a part of the very curriculum; rather they are supplementary (Zins et al., 2004). These narrow approaches seem to undermine the holistic development of the students curtail them from becoming ready to face the real world challenges.

### **3. Problematic Assessment-**

Traditional assessment procedures developed to track success in the academic world do not well portray the transformation that has occurred in the lives of the learners. Many teachers lack a mechanism to evaluate the life skills, such as emotional control, cooperation, and solving problems. In this respect, where there are no effective assessment procedures, the implementation of few life skills into evaluation procedures in education may lead to little significance of these skills in the class room.

### **4. Inadequate Material Resources-**

Little finances and poor material resources make life skills integration even more difficult. Schools might not have adequate finances to plan and implement proper holistic life skills programs or even get access to material and training on them. This inadequacy leads to piecemeal attempts that do not result in a holistic approach toward life skills education.

### **5. Resistance to Change-**

Lastly, resistance among the teachers and other administrators creates a hindrance to introducing life skills in the curriculum. There might be people who feel that life skills will become less important in the heads of the students since academic subjects are valued more. This therefore gives the teachers and other administrators a tendency not to embrace new methods of teaching. This requires constant advocacy or convincing and giving clear evidence of life skills benefitting the general success of the students. It is against this backdrop that a common collaboration by educators, policymakers, and all other stakeholders in creating a framework that supports the implementation of life skills in schools ought to be created.

### **Conclusion-**

Integrating life skills into the curriculum of education is necessary because it implements holistic education that readies children to meet the complexity and dynamism of the changing global world. Since the paradigms of conventional education have shifted, knowledge learned in the classrooms alone is not enough for survival or even survival and success in life or work. Life skills-integrative competencies, such as critical thinking, communication, emotional regulation, and problem-solving, are essential skills with which they are empowered to face the challenges of modern life triumphantly. This paper discusses the theoretical frameworks underpinning the integration of life skills in education, which is found in constructivist learning theories as well as SEL frameworks. These studies emphasize experiential learning as well as emotional intelligence in support of an educational approach that feeds into cognitive, emotional, and social dimensions of student development. Embedding the life skills component into subjects provides relevant, challenging, and engaging learning experiences for the students and contributes to their holistic development. Despite these significant benefits that life skills can bring by being added to the curriculum, some challenges persist. Lack of teacher training, curriculum overload, assessment issues, and lack of resources are a few of the barriers that have prevented such an effective implementation process. All these demand collaboration among educators, policymakers, and other stakeholders for the fight to achieve life skills education as pivotal in the modern curricula. Thorough training of teachers blended with creative curriculum mapping and cross-disciplinary designs can make life skills work well.

Teaching life skills contributes to improved academic performance and comes handy as tools which facilitate long-term change in the challenges of real life. Education evolves over time, and one of the key roles that it will have in determining resilient, adaptable individuals with a capability to thrive in an unrelenting dynamic landscape is going to be life skills. Such an all-round approach towards education can help better equip future generations for lifelong success and well-being, helping them to become positive contributors to their communities and society at large. It is not optional but necessary to integrate life skills into learning, for it would be impossible to make leaders or problem-solvers of tomorrow without life skills integrated into learning.

## References-

- 1-Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432. (p. 415-420) .  
<https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x>
- 2-Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International Universities Press. (p. 89-92)
- 3-Rimm-Kaufman, S. E., & Sandilos, L. E. (2012). The role of social and emotional learning in teacher education. *Journal of Teacher Education*, 63(3), 251-261.  
<https://doi.org/10.1177/0022487111431440>
- 4-Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press. (p. 79-81)
- 5-Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design*. ASCD. (p. 57-63)
- 6-World Health Organization. (1993). *Life skills education for children and adolescents in schools*. Geneva: WHO. (p. 25-30) <https://www.who.int/publications/i/item/9241561926>
- 7-WHO (1997). *Meaning of Life Skills*. Retrieved from [www.who.org/lis](http://www.who.org/lis).
- 8-Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?* Teachers College Press. (p. 110-115).

## भारत में शिक्षक-शिक्षा का भविष्य: उभरती कार्य-पद्धतियाँ और प्रतिमान

\*संजय कुमार प्रजापति

\*\*डॉ० संदीप कुमार श्रीवास

### शोध सार

तकनीकी प्रगति और बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के कारण भारत में शिक्षा का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। इस संदर्भ में शिक्षकों की भूमिका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिसके लिए शिक्षक शिक्षा प्रथाओं में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। यह शोधपत्र भारत में शिक्षक प्रशिक्षण को नया आकार देने वाली उभरती कार्य पद्धतियाँ और प्रतिमान के साथ-साथ उसके संभावित निहितार्थों और भविष्य की दिशाओं की पड़ताल करता है। यह वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करता है, जैसे व्यावहारिक कौशल और पुराने पाठ्यक्रम पर सीमित ध्यान और अनुभवात्मक शिक्षा, प्रौद्योगिकी एकीकरण और सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा को प्राथमिकता देने सहित नवीन समाधान प्रस्तावित करता है। इसके अतिरिक्त यह शिक्षक शिक्षा को नए सिरे से तैयार करने, शिक्षार्थी-केन्द्रित दृष्टिकोण, ज्ञान अनुप्रयोग और सहयोगात्मक शिक्षा की ओर बढ़ने के उभरते प्रतिमानों पर चर्चा करता है। शोधपत्र में शिक्षक शिक्षा के विकास के संभावित निहितार्थों की भी जाँच की गई है, जिसमें छात्रों के सीखने के बेहतर परिणाम और शिक्षा में अधिक समानता शामिल है। अंत में यह भारत में शिक्षक शिक्षा के लिए भविष्य की दिशाओं की रूपरेखा तैयार करता है, प्रौद्योगिकी एकीकरण योग्यता-आधारित मॉडल और वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। कुल मिलाकर यह शोधपत्र शिक्षकों को सशक्त बनाने और उन्हें 21 वीं सदी की कक्षा की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए नवाचार और निरंतर सुधार को अपनाने के महत्व पर जोर देता है।

**कूट शब्द:** शिक्षक-शिक्षा, भारत, उभरती कार्य पद्धतियाँ, प्रतिमान एवं बदलाव।

### प्रस्तावना:

भारत की शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही हैं अब शिक्षक केवल ज्ञान के प्रसारण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, शिक्षक सीखने के वास्तुकार बनने के लिए तैयार हैं, जो आकर्षक अनुभव तैयार करते हैं जो छात्रों को 21 वीं सदी की जटिलताओं के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए शिक्षक शिक्षा में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है, यह क्षेत्र संभावनाओं से भरपूर है। यह शोधपत्र भारत में शिक्षक प्रशिक्षण का नया आकार देने वाली उभरती कार्य-पद्धतियाँ और प्रतिमानों के साथ-साथ इस महत्वपूर्ण डोमेन के संभावित निहितार्थों और आशाजनक भविष्य की दिशाओं की पड़ताल करता है। (ब्रांसफोर्ड, डोनोवन, और पेलेग्रिनो, 2000; एनईपी0, 2020) आवश्यक कौशल और दृष्टि से सशक्त शिक्षकों की एक नयी पीढ़ी को बढ़ावा देकर, भारत अपनी शिक्षा प्रणाली की अपार संभावनाओं को उजागर कर सकता है,

\* (शोधार्थी), शिक्षक-शिक्षा विभाग, प्रो० एच०एन० मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कानपुर, उ०प्र०,

**Email:- sanjayprajapti91@gmail.com**, मो०नं०-9795226920

\*\*सहायक आचार्य, शिक्षक-शिक्षा विभाग, प्रो०एच०एन० मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कानपुर, उ०प्र०, **Email:-sandeep.srivastava2@gmail.com**, मो०नं०-9415926149



छात्रों को तेजी से विकसित हो रही दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाना। शिक्षा का परिदृश्य निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, जो प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति, बढ़ती सामाजिक जरूरतों और छात्रों को एक गतिशील और अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार करने पर बढ़ते जोर से प्रेरित है इस निरंतर विकास के लिए हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और उन्हें सुसज्जित करने के तरीके में एक समानांतर परिवर्तन की आवश्यकता होती है। शिक्षक शिक्षा के पारंपरिक मॉडल, मूल्यावान होते हुए भी अब 21 वीं सदी की कक्षा की माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

### परिवर्तन की आवश्यकता:

मौजूदा शिक्षक शिक्षा मॉडल की कमियाँ अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। आलोचक अक्सर ऐसे पाठ्यक्रम की ओर इशारा करते हैं जो अत्यधिक सैद्धांतिक हैं और कक्षा की वास्तविकताओं से अलग हैं (डार्लिंग-हैमंड, 2006)। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक कार्यक्रम वैश्विक छात्र आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने या सीखने को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त रूप से तैयार नहीं कर सकते हैं (फ्रीडमैन, 2006)। यह शोधपत्र तर्क देता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक आदर्श बदलाव आवश्यक है कि शिक्षकों की भावी पीढ़ियों के पास सभी छात्रों के लिए एक संपन्न सीखने का माहौल तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हो। रेजीडेंसी कार्यक्रमों, प्रौद्योगिकी-एकीकृत निर्देश और सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने जैसे नवीन दृष्टिकोणों पर ध्यान देकर, हम शिक्षकों की एक नयी पीढ़ी को बढ़ावा दे सकते हैं जो न केवल विषय वस्तु में पारंगत है बल्कि महत्वपूर्ण सोच, सहयोग को बढ़ावा देने में भी माहिर हैं।

### शोध पत्र की संरचना:

यह शोधपत्र तीन खण्डों में विभाजित है। पहला खण्ड-भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के सामने प्रमुख चुनौतियाँ। दूसरा खण्ड-भारत में शिक्षक शिक्षा को नया आकार देने वाली उभरती प्रथाएँ (प्रवृत्ति)। तीसरा खण्ड-भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास के संभावित निहितार्थ।

### भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के सामने आ रही प्रमुख चुनौतियाँ:

भारत की शिक्षा प्रणाली विशाल और महत्वाकांक्षी होते हुए भी 21 वीं सदी की कक्षा की माँगों के लिए अपने शिक्षकों को तैयार करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती है। यहाँ शोधकर्ता कुछ प्रमुख बाधाओं का पता लगाता है जिन्हें वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से दूर करना होगा। (सिंह और सिंह, 2018, कुमार और पंवार, 2017, यादव, 2016, मित्तल, 2013)।

1. **व्यावहारिक कौशल पर सीमित फोकस:** कई कार्यक्रम व्यावहारिक अनुप्रयोग पर सैद्धांतिक ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं। यह कक्षा प्रबंधन, विभेदित निर्देश और विविध शिक्षण शैलियों की वास्तविकताओं के लिए तैयार नहीं करता है।

2. **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संसाधन:** शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अक्सर पर्याप्त धन की कमी होती है, जिसके कारण योग्य प्रशिक्षकों की कमी, पुरानी शिक्षण सामग्री और अपर्याप्त तकनीकी संसाधन होते हैं। यह प्रशिक्षण की गुणवत्ता में बाधा डालता है और नवीन शिक्षण विधियों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है।

3. **पुराना पाठ्यक्रम:** कुछ कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम नवीनतम् शैक्षिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है या प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत नहीं कर सकता है। यह डिस्कनेक्ट शिक्षक तथा छात्रों को शामिल करने और उन्हें डिजिटल उपकरणों से अत्यधिक प्रभावित भविष्य के लिए तैयार करने के लिए अयोग्य बना सकता है।

4. **सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा पर सीमित जोर:** शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अक्सर सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा (Social Emotional) के महत्त्व को नजरअंदाज कर देते हैं। यह उपेक्षा शिक्षकों को अपने छात्रों की भावनात्मक भलाई को संबोधित करने के लिए तैयार नहीं करती है, जो सकारात्मक सीखने के माहौल को बढ़ावा देने और शैक्षिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।

5. **शिक्षक प्रशिक्षकों की गुणवत्ता:** उच्च योग्य और अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकों की कमी भी एक कारण हो सकता है, जो संभावित रूप से इच्छुक शिक्षकों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा और मार्गदर्शन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

6. **माँग और आपूर्ति के बीच समन्वय न होना:** शिक्षा क्षेत्र के तेजी से विस्तार के कारण योग्य शिक्षकों की माँग और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों से स्नातकों की संख्या के बीच बेमेल हो गया है। इसके परिणामस्वरूप कम तैयारी वाले या अयोग्य व्यक्ति इस पेशे में प्रवेश कर सकते हैं।

7. **सतत् व्यावसायिक विकास का अभाव:** कई कार्यक्रमों में चल रहे व्यावसायिक विकास के लिए एक संरचित प्रणाली का अभाव होता है, जिससे शिक्षकों को अपने कौशल को अनुकूलित करने और नवीनतम् शैक्षिक प्रगति से अवगत रहने के सीमित अवसर मिलते हैं। इन चुनौतियों से निपटना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण है कि भारत शिक्षकों की भावी पीढ़ी तैयार करे जो छात्रों को वैश्विक और लगातार विकसित हो रही दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से प्रभावी ढंग से तैयार कर सके।

### भारत में शिक्षक शिक्षा को नया आकार देने वाली उभरती कार्य-पद्धतियाँ:

भारत में शिक्षक शिक्षा परिदृश्य कायापलट के दौर से गुजर रहा है, जो 21 वीं सदी की कक्षा की माँगों के लिए शिक्षकों को तैयार करने की बढ़ती आवश्यकता से प्रेरित हैं। यहाँ शोधकर्ता शिक्षक प्रशिक्षण के भविष्य को आकार देने वाली कुछ सबसे आशाजनक उभरती कार्य-पद्धतियों पर प्रकाश डालता है (सीबीएसई, 2020, एमएचआरडी), 2018; यूजीसी, 2018;

1. **अनुभवात्मक शिक्षा को अपनाना:** विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक शिक्षा से अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना शिक्षक शिक्षा को नया आकार दे रहा है। कार्यक्रमों में रेजीडेंसी स्कूल-आधारित इंटरशिप और प्रैक्टिकम को शामिल किया जा रहा है, जो इच्छुक शिक्षकों को वास्तविक दुनिया की कक्षाओं में अनुभवी मेंटर के साथ रखता है। इससे उन्हें कक्षा प्रबंधन, पाठ योजना और छात्र विविधता को नेविगेट करने, व्यावहारिक कौशल को बढ़ावा देने और शिक्षण की जटिलताओं की गहरी समझ के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

2. **उपकरण और सहयोगी के रूप में प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** शिक्षा में प्रौद्योगिकी की सर्वव्यापी उपस्थिति शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को अपने पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिक उपकरणों और संसाधनों को एकीकृत करने के लिए प्रेरित कर रही है। यह बुनियादी कम्प्यूटर साक्षरता से आगे जाता है। कार्यक्रम शिक्षकों को प्रभावी पाठ योजना, विभेदित निर्देश और छात्रों में डिजिटल साक्षरता

को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के कौशल से निपुण करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इसमें सिमुलेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, शैक्षिक ऐप्स, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड यहाँ तक कि आभासी वास्तविकता (वीआर) का उपयोग करना शामिल हो सकता है।

3. **सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा (एसईएल) को प्राथमिकता देना:** संपूर्ण बच्चे के पोषण के महत्त्व को पहचानते हुए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम एसईएल को एकीकृत कर रहे हैं। सिद्धांत रूप में यह भावी शिक्षकों को अपने छात्रों की भावनात्मक भलाई को संबोधित करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित करता है। इसमें सकारात्मक कक्षा वातावरण बनाने, स्व-नियमन और सामाजिक कौशल विकास को बढ़ावा देने और स्वयं तथा उनके छात्रों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए सीखने की रणनीतियाँ शामिल हैं। इससे छात्रों की व्यस्तता में सुधार हो सकता है, व्यवहार संबंधी समस्याएँ कम हो सकती हैं और सभी के लिए अधिक सहायक सीखने का माहौल बन सकता है।

4. **विकास के लिए सहयोगात्मक शिक्षण और परामर्श :** सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण और मजबूत परामर्श कार्यक्रमों की ओर एक कदम इच्छुक शिक्षकों के लिए अधिक सहायक और इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव को बढ़ावा दे रहा है। सहकर्मी से सहकर्मी शिक्षण ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान की अनुमति देता है, जबकि अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन अमूल्य अंतर्दृष्टि और समर्थन प्रदान करता है। शिक्षार्थियों का समुदाय बनाना जहाँ शिक्षक सहयोग कर सकें, सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को साझा कर सकें और एक-दूसरे से सीख सकें, निरंतर सुधार और पेशेवर विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है।

5. **सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी):** यह समझ कि स्नातक होने के बाद सीखना बंद नहीं होता है, निरंतर व्यावसायिक विकास (सीपीडी) पर जोर बढ़ रहा है। कार्यक्रम और पहल शिक्षकों को कार्यशाला, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, पेशेवर शिक्षण समुदाय (पीएलसी) और सम्मेलनों जैसे चल रहे सीखने के अवसरों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह शिक्षकों को विकसित हो रही शैक्षिक कार्य-पद्धतियाँ शिक्षाशास्त्र और प्रौद्योगिकी में प्रगति से अवगत रहने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपने कैरियर के दौरान प्रभावी शिक्षक बने रहें।

6. **कार्य-पद्धतियाँ से परे:** एक आदर्श बदलाव को अपनाना, ये उभरती कार्य-पद्धतियाँ एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत में शिक्षक शिक्षा के प्रतिमान का ध्यान केवल ज्ञान प्रदान करने से हटकर एक अच्छा विकास करने पर है— एक निपुण शिक्षक जिसके पास न केवल विषय-वस्तु विशेषज्ञता है बल्कि शैक्षिक कौशल तथा तकनीकी कौशल भी है, सभी छात्रों के लिए एक समृद्ध सीखने का माहौल बनाने के लिए प्रवास और सामाजिक-भावनात्मक बुद्धिमत्ता आवश्यक है।

इन कार्य पद्धतियों (Practices) को अपनाकर और निरंतर सीखने और अनुकूलन की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारतीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों की भावी पीढ़ी को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो शिक्षा के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करने और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने हेतु अच्छी तरह से सुसज्जित तथा 21वीं सदी हेतु तैयार कर सकते हैं।

**उभरते प्रतिमान: भारत में शिक्षक शिक्षा को नया स्वरूप देना**

भारत में शिक्षक शिक्षा का भविष्य केवल नयी कार्य-पद्धतियों को शामिल करने के बारे में नहीं है। यह शिक्षकों को देखने और तैयार करने के हमारे तरीके में मूलभूत बदलाव लाने के बारे में है। यहाँ शोधकर्ता कुछ उभरते हुए प्रतिमानों की खोज करता है जो परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं (शुलमैन, 1987, एनसीएफ, 2005, फुलान, 2007, झाओ, 2018)

1. **शिक्षक—केन्द्रित से शिक्षार्थी—केन्द्रित तक:** पारंपरिक मॉडल अक्सर शिक्षक को केन्द्र में रखते हैं। सीखने का आरोप है कि नया प्रतिमान शिक्षार्थी केन्द्रित दृष्टिकोण पर जोर देता है, जहाँ इच्छुक शिक्षक छात्र—संचालित शिक्षा को सुविधाजनक बनाने और विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कौशल विकसित करते हैं। इसमें आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना शामिल है। अपने छात्रों में सहयोग और समस्या—समाधान कौशल उन्हें एक ऐसी दुनिया में सफलता के लिए तैयार करना जो अनुकूलनशीलता और नवीनता की माँग करती है।

2. **ज्ञान अर्जन से ज्ञान अनुप्रयोग:** केवल विषय—वस्तु ज्ञान प्राप्त करने से हटकर उस ज्ञान को कक्षा में प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता विकसित करने पर केन्द्रित है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक ढाँचे को शामिल कर रहे हैं, जो इच्छुक शिक्षकों को अपनी विशेषज्ञता को आकर्षक और इंटरैक्टिव पाठ योजनाओं में अनुवाद करने के कौशल से तैयार करते हैं, जो उनके छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह छात्रों के लिए ज्ञान की गहरी समझ और उसे बनाए रखना सुनिश्चित करता है।

3. **पाठ्यचर्या डिजाइन के लिए सामग्री वितरण:** शिक्षकों का पारंपरिक मॉडल पूरी तरह से पूर्व—डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम को विकसित करना, एक ऐसे प्रतिमान का मार्ग प्रशस्त कर रहा है जो पाठ्यक्रम डिजाइन कौशल पर जोर देता है। भावी शिक्षकों को सृजन के लिए सशक्त बनाया जाएगा। आकर्षक और अनुकूलनीय अग्रणी अनुभव जो स्थानीय संदर्भ के लिए प्रासंगिक है और 21 वीं सदी के कार्यस्थल की उभरती जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें परियोजना—आधारित शिक्षा को एकीकृत करना, प्रौद्योगिकी उपकरणों को शामिल करना और कक्षा में पूछताछ और अन्वेषण की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

4. **निष्क्रिय उपभोक्ता से सक्रिय सहयोगी:** शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम इच्छुक शिक्षकों के बीच सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में निष्क्रिय, व्याख्यान—आधारित दृष्टिकोण से दूर जा रहे हैं। इसमें सहकर्मी शिक्षण, समूह चर्चा और समस्या—समाधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, महत्वपूर्ण सोच और संचार कौशल के विकास को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त मेंटरशिप कार्यक्रम के माध्यम से अनुभवी शिक्षकों के साथ सहयोग से ज्ञान साझा करने और एक सहायक पेशेवर नेटवर्क के विकास की अनुमति मिलती है।

5. **अलग—थलग पेशेवर से जुड़े शिक्षक:** अलग—थलग शिक्षक के प्रतिमान को ऑनलाइन समुदायों, पेशेवर शिक्षण नेटवर्क (पीएलएन) और सहयोगी प्लेटफार्मों के उदय से चुनौती दी जा रही है। ये उपकरण भावी शिक्षकों को भौगोलिक सीमाओं के पार सहकर्मियों के साथ जुड़ने, सर्वोत्तम कार्य—पद्धतियाँ को साझा करने और अपने पूरे कैरियर में निरंतर व्यावसायिक विकास में संलग्न रहने की अनुमति देते हैं। यह शिक्षकों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है और आजीवन सीखने की सुविधा प्रदान करता है।

6. **शिक्षक एक परिवर्तन एजेंट के रूप में :** ये उभरते प्रतिमान एक भावी शिक्षक की तस्वीर चित्रित करते हैं जो सिर्फ एक शिक्षक नहीं है। ज्ञान प्रदान करने वाला लेकिन सीखने में सहायक, पाठ्यक्रम डिजाइनर और सहयोगी। वे परिवर्तन के एजेंट हैं, जो गतिशील और समावेशी शिक्षण वातावरण बना सकते हैं, अपने छात्रों में सीखने के प्रति प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं, उन्हें वैश्वीकृत दुनिया के महत्वपूर्ण विचारक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाना।

इन प्रतिमानों को अपनाकर, भारतीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम केवल शिक्षकों को तैयार करने से आगे बढ़ सकते हैं, वे उन्हें भविष्य-प्रूफ शिक्षा प्रणाली के वास्तुकार बनने के लिए कौशल और दृष्टि से लैस कर सकते हैं जो छात्रों को आगे बढ़ने के लिए सभी को सशक्त बनाता है।

### **भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास के संभावित निहितार्थ:**

भारत में शिक्षक शिक्षा का परिवर्तन देश के शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देने की अपार संभावनाएँ रखता है। यहाँ शोधकर्ता इन उभरते रुझानों के कुछ प्रमुख निहितार्थों का पता लगाता है (एनआईईपीए, 2016; आइंस्को, 2014; मित्तल, 2013; वाचोवेजक, 2011; डेसिमोन, 2009)

1. **छात्रों के बेहतर सीखने के परिणाम** : शिक्षकों को मजबूत शैक्षिक कौशल, तकनीकी प्रवाह से लैस करना और सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने से छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार हो सकता है। छात्रों को आकर्षक ओर इंटरैक्टिव अध्यायों से लाभ होगा जो महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और सहयोग कौशल को बढ़ावा देंगे।

2. **शिक्षक की नौकरी छोड़ने की दर में कमी**: शिक्षक प्रशिक्षण के लिए व्यावहारिक और सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रदान करके, कार्यक्रम नौकरी से असंतोष और थकान जैसे मुद्दों का समाधान कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से शिक्षक नौकरी छोड़ने की दर में कमी आ सकती है। इससे छात्रों के लिए सीखने के माहौल में अधिक स्थिरता और निरंतरता आती है।

3. **बेहतर शिक्षक गुणवत्ता और प्रभावशीलता** : योग्यता-आधारित शिक्षा और निरंतर व्यावसायिक विकास पर ध्यान एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुकूलनीय शिक्षण कार्यबल सुनिश्चित करता है। इससे देश भर में शिक्षा वितरण का स्तर ऊँचा होगा, जिससे सभी पृष्ठभूमि के छात्रों को लाभ होगा।

4. **अधिक समानता और समावेशन** : शिक्षकों को विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करने और सभी छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के कौशल से लैस करके शिक्षक शिक्षा सुधार शिक्षा प्रणाली में अधिक समानता और समावेशन को बढ़ावा दे सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को पृष्ठभूमि या क्षमता की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने का अवसर मिले।

5. **सशक्त और संलग्न शिक्षक** : उभरते प्रतिमान जो सहयोग, आजीवन सीखने और सक्रिय भागीदारी पर जोर देते हैं, भविष्य के शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली के भीतर परिवर्तन एजेंट बनने के लिए सशक्त बना सकते हैं। यह अधिक भावुक और संलग्न शिक्षण कार्यबल को बढ़ावा देता है, जिससे शैक्षिक कार्य-पद्धतियों में निरंतर सुधार और नवाचार होता है।

### **चुनौतियाँ और विचार:**

1. **प्रभावी कार्यान्वयन** : इन सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें बुनियादी ढाँचे की सीमाओं को संबोधित करना, शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करना और नए योग्य शिक्षकों के लिए मजबूत समर्थन प्रणाली सुनिश्चित करना शामिल है।

2. **सहयोग और साझेदारी** : प्रभावी परिवर्तन के लिए सरकारी अभिकरण, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, विद्यालय और शैक्षिक अनुसंधान संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों के अनुरूप हों और शिक्षा प्रणाली की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करें।

3. **मौजूदा शिक्षक कार्यभार को संबोधित करना** : नयी शिक्षा पद्धतियों को लागू करने के लिए शिक्षकों को अतिरिक्त समय और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। मौजूदा कार्यभार संबंधी चिंताओं को दूर करना और पर्याप्त सहायता प्रदान करना सुचारु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है।

कुल मिलाकर शिक्षक शिक्षा का उभरता परिदृश्य एक मजबूत और भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रणाली बनाने का एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है। इन उभरते रुझानों की क्षमता का लाभ उठाकर और संबंधित चुनौतियों का समाधान करके भारत अपने शिक्षकों को वैश्विक नागरिकों की अगली पीढ़ी का पोषण करने के लिए सशक्त बना सकता है।

### **भारत में शिक्षक शिक्षा की भावी दिशाएँ: एक संपन्न शिक्षा को आकार देना**

भारत में शिक्षक शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन की बयार बह रही है, जो 21वीं सदी की कक्षा की माँगों के लिए शिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता से प्रेरित है, यहाँ शोधकर्ता भविष्य की कुछ संभावित दिशाओं का पता लगाता है जो यह महत्वपूर्ण क्षेत्र ले सकता है (सीआईईटी, 2021; एनसीईआरटी, 2019; यूनेस्को, 2015)

1. **प्रौद्योगिकी एकीकरण पर फोकस गहराना:** प्रौद्योगिकी अब एक वैकल्पिक उपकरण नहीं है; यह आधुनिक शिक्षा का एक मूलभूत पहलू है। भविष्य की दिशाओं में शैक्षिक प्रौद्योगिकी (एजुटेक) पर पाठ्यक्रमों को पाठ्यक्रम में गहराई से एकीकृत करना शामिल हो सकता है, न केवल बुनियादी कौशल पर, बल्कि प्रौद्योगिकी शैक्षिक अनुप्रयोगों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है। इसमें वैयक्तिकृत शिक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.), इमर्सिव सिमुलेशन के लिए आभासी वास्तविकता (वीआर) और इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभवों के लिए सर्वोत्तम वास्तविकता (एआर) के उपयोग की खोज शामिल हो सकती है।

2. **निरंतर सुधार के लिए योग्यता—आधारित मॉडल को अपनाना:** योग्यता—आधारित शिक्षक शिक्षा मॉडल की ओर बदलाव जोर पकड़ रहा है। ये कार्यक्रम प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल और ज्ञान सेट विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जिनका मूल्यांकन प्रदर्शन—आधारित उपायों के माध्यम से किया जाता है। इस भविष्य की दिशा में कक्षा के अवलोकन छात्रों के सीखने के परिणाम और शिक्षक के विचारों के आधार पर चल रहे मूल्यांकन शामिल हो सकते हैं, जिससे शिक्षकों के लिए निरंतर सुधार चक्र तैयार हो सकता है।

3. **पूछताछ और अनुसंधान की संस्कृति का पोषण:** शिक्षकों के बीच एक अनुसंधान—उन्मुख दृष्टिकोण विकसित करने से अधिक साक्ष्य—आधारित और डेटा—संचालित शिक्षा प्रणाली बन सकती है। भविष्य के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम इच्छुक शिक्षकों को नवीन प्रथाओं का पता लगाने और कक्षा में उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए साथियों और शैक्षिक शोधकर्ताओं के साथ सहयोग करके कार्यवाही में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

4. **वैयक्तिकृत शिक्षण मार्ग:** भावी शिक्षकों, भावी कार्यक्रमों की विविध आवश्यकताओं और रुचियों को पहचानना, लचीले और वैयक्तिकृत शिक्षण मार्ग प्रदान कर सकता है। इसमें ऑनलाइन मॉड्यूल, मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण और विशेष ऐच्छिक शामिल हो सकते हैं, जो शिक्षकों को उनकी विशिष्ट कैरियर आकांक्षाओं और शिक्षण संदर्भों के अनुसार अपनी शिक्षा को तैयार करने की अनुमति देते हैं।

5. **वैश्विक सहयोग और ज्ञान विनिमय:** शिक्षा का भविष्य स्वाभाविक रूप से वैश्विक है। भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थानों और उनके वैश्विक के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान विनिमय कार्यक्रम समकक्ष इच्छुक शिक्षकों के लिए अधिक गतिशील और नवीन शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें शामिल हो सकता है— संयुक्त पाठ्यक्रम विकास, छात्र विनिमय कार्यक्रम और शिक्षकों के साथ दुनियाभर में ऑनलाइन सीखने के अवसर।

6. **विद्यालय-विश्वविद्यालय साझेदारी को मजबूत करना:** शिक्षक शिक्षा संस्थान और विद्यालयों के बीच मजबूत साझेदारी का निर्माण इच्छुक शिक्षकों के लिए सिद्धांत से अभ्यास तक अधिक सहज संक्रमण पैदा कर सकता है। भविष्य की दिशाओं में नवीन प्रथाओं, सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं का सह-निर्माण और कार्यान्वयन शामिल हो सकता है।

व्यावसायिक विकास विद्यालयों की स्थापना करना, जहाँ शिक्षक प्रशिक्षक और अनुभवी शिक्षक भावी पीढ़ियों को सलाह देने के लिए मिलकर काम करते हैं।

ये संभावित दिशाएँ एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करती हैं, जहाँ भारत में शिक्षक शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक शिक्षक में एक गंभीर रूप से चिंतनशील, तकनीकी रूप से निपुण और आजीवन सीखने वाले का पोषण करने के बारे में है। भविष्य की इन दिशाओं को अपनाकर और निरंतर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान भविष्य के शिक्षकों को शिक्षा के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करने और छात्रों को एक गतिशील और परस्पर जुड़ी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टि से लैस कर सकते हैं।

### निष्कर्ष:

भारत में शिक्षक शिक्षा का भविष्य परिवर्तन और विकास के अवसरों से भरपूर है। इस शोध पत्र में चर्चा की गई उभरती कार्य-पद्धतियाँ और प्रतिमान शिक्षक के एक नए युग की झलक पेश करते हैं, जो व्यावहारिक कौशल, तकनीक प्रवाह और सामाजिक-भावनात्मक शिक्षा पर जोर देता है। वर्तमान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके और नवीन दृष्टिकोण अपनाकर, भारत अधिक गतिशील और समावेशी शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारत में शिक्षक शिक्षा के विकास के संभावित निहितार्थ दूरगामी हैं, जिनमें छात्रों के सीखने के परिणामों में वृद्धि से लेकर शिक्षकों के नौकरी छोड़ने की दर में कमी और शिक्षक की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार शामिल है। हालाँकि इन सकारात्मक परिणामों को साकार करने में विभिन्न हितधारकों के बीच प्रभावी कार्यान्वयन और सहयोग महत्वपूर्ण होगा। आगे देखते हुए, भारत में शिक्षक शिक्षा की भविष्य की दिशाएँ प्रौद्योगिकी के गहन एकीकरण, निरंतर सुधार के लिए योग्यता-आधारित मॉडल, पूछताछ और अनुसंधान की संस्कृति का पोषण, व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग, वैश्विक सहयोग और विद्यालय-विश्वविद्यालय साझेदारी को मजबूत करने का वादा करती हैं। भविष्य की इन दिशाओं को अपनाकर और निरंतर नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर भारतीय शिक्षक शिक्षा संस्थान भविष्य के शिक्षकों को शिक्षा के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करने और छात्रों को एक गतिशील और परस्पर जुड़ी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने हेतु आवश्यक कौशल और दृष्टि से लैस कर सकते हैं।

### संदर्भ ग्रंथ सूची

- Ainscow, M. (2014). From special education to effective schools for all. Widening the agenda.
- Bransford, J. D., Donovan, S., & Pellegrino, J. W. (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School (Expanded Edition). Washington, DC: National Academies Press
- Central Board of Secondary Education (CBSE). (2020). *Guidelines for Integration of Life Skills in CBSE Schools*. New Delhi, India.
- Central Institute of Educational Technology (CIET), (2021). *Handbook on effective use of ICT in teacher education*. New Delhi, India.
- Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-Century Teacher Education, *Journal of Teacher Education*, 57 (3).<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022487105285962>
- Desimone, L. (2009). *Improving teacher effectiveness in an era of accountability*. Educational Researcher, 38(8), 18-24.

- Friedman, I. A. (2006). Classroom Management and Teacher Stress and Burnout. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), *Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues* (pp. 925–944). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Fullan, M. (2007). The Limitations Impacting Teachers’ Understanding of Creative Thinking, *Creative Education*, 10(7).<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1802900>
- Kumar, S., & Panwar, M. (2017). Teacher education in India: Issues and challenges. *International Journal of Research in Humanities and Social Sciences*, 5(7), 182-188.
- Ministry of Human Resource Development (MHRD). (2018). *Scheme for Integrating ICT in Schools (SIICT)*. New Delhi, India.
- Mittal, A. (2013). Quality teacher education in India: Challenges and strategies. *Journal of Educational Research and Development*, 11(1), 1-10.
- National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2019). *Framework for teacher education curriculum*. New Delhi, India.
- National Curriculum Framework 2005. (2005). *National Council of Educational Research and Training (NCERT)*. New Delhi, India.
- National Education Policy (NEP) 2020. (2020). Ministry of Education, Government of India.
- National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA). (2016). *Teacher education in India: Issues, challenges and recommendations*. New Delhi, India
- Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14.
- Singh, A., & Singh, J. (2018). Need for social and emotional learning in teacher education. *International Journal of Research in Education and Development*, 6(2), 561-565.
- UNESCO. (2015). *Education 2030: Towards inclusive and sustainable development*. Paris, France.
- University Grants Commission (UGC). (2018). *Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges (12th Biennial Update)*. New Delhi, India.
- Wachowczak, G. (2011). Teacher workload: An overview of the research. *Review of Educational Research*, 81(2)
- Yadav, R. (2016). Challenges in teacher education in India: Need for reforms. *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 3(5), 118-120.
- Zhao, Y. (2018). Teacher professional learning in the digital age: *Building capacity through online professional learning communities*. *Educational Researcher*, 47(7), 408-420.



## AWARENESS ON CYBER SECURITY AMONG PUPIL TEACHERS IN MEERUT DISTRICT

\*Rashmi Yadav

### ABSTRACT

*The increasing use of technology in education has invented new opportunities for learning but also create cyber security risks. The increasing reliance on digital technology in educational institutions has heightened the need for pupil teachers to be aware of cyber security threats and best practices. This study aimed to investigate the level of awareness about cyber security among pupil teachers in Meerut district on the basis of gender and their graduation subjects . It is a descriptive survey research which is quantitative in nature. The study was conducted on a sample size of 100 pupil teachers who were studying in self – finance B.Ed. colleges of Meerut district. A questionnaire constructed and validated by the researcher was used as the tool for the study. The statistical techniques such as **Mean, Standard Deviation and t- Test** were employed to analyze the data. The findings of the study tells us that the pupil teachers have average level of awareness on cyber security and both male and female pupil teachers have same level of awareness on cyber security but the pupil teachers who graduated in computer science /information technology have higher level of awareness on cyber security than the pupil teachers who graduated in other subjects.*

**Keywords – Cyber Security , Digital Literacy, Awareness,**

### Introduction

The rapid integration of digital technology in educational institution has transformed the way pupil teachers interact with students and use the educational resources. However this increase reliance on digital technology has also introduced new risks and vulnerabilities particularly in the field of cyber security. Technology has its own pros and cons. The demand of using technical gadgets in the field of education is increasing day by day. Cyber security threats such as **malware, phishing, ransomware, viruses, Trojans, spyware** are most common. To avoid these threats, one need to aware about some cyber security measures such as **firewalls, antivirus software, encryption, use strong password, two – factor authentication (2FA), regular software updates**. As pupil teachers play an important role in shaping the digital literacy that they possesses a robust understanding of cyber security principles and best practices.

The most significant threat to cyber security is not the technology itself but the lack of awareness and education among users. As pupil teachers, they play a critical role in shaping the digital habits of future generation.

Pupil teachers act as a bridge between student and teacher. As we all know that cyber security is not just a technical issue, it is a human issue and pupil teachers have a responsibility to ensure that their students are equipped with the knowledge and skills to navigate the digital world safely. Therefore it is essential that they have a good understanding of cyber security principles and best practices.

---

**Research Scholar, Department of Education, (Meerut College, Meerut) Email -1993rashmiyadav@gamil.com, Mob.No. 7017100798**

Despite the importance of cyber security awareness among pupil teachers, there is a lack of research on this topic. This study ends to fill this knowledge gap by investigating pupil teachers' knowledge, perception and practices related to cyber security.

### **Significance of the study**

The significance of the study about awareness on cyber security among pupil teachers has been divided into the following three forms on the basis of it's nature.

#### **1. Practical Significance**

##### **1.1 Improved Cyber Security Practices**

By Understanding the current level of awareness and knowledge about cyber security among pupil teachers the study can inform the development of targeted training program to improve their cyber security practices.

##### **1.2 Enhanced Protection of Students' Data**

Pupil teachers play a critical role in handling sensitive student data. By enhancing their awareness and knowledge about cyber security the study can contribute to the protection of the student data and prevent potential cyber security breaches.

##### **1.3 Better Digital Citizenship**

The study can inform the development of digital citizenship programs that promote responsible and safe online behavior among pupil teachers and their students.

#### **2. Theoretical Significance**

##### **2.1 Contribution to Cyber Security Literature**

The study can contribute to the existing body of literature on cyber security awareness and knowledge among educators particularly pupil teachers.

##### **2.2 Development of Theoretical Frameworks**

The study can inform the development of theoretical frameworks that explain the relationship between cyber security awareness, knowledge and practices among pupil teachers.

##### **2.3 Understanding of Cyber Security Awareness**

The study can provide insights into the factors that influence cyber security awareness among people teachers including demographic characteristics training and experience.

#### **3. Social Significance**

##### **3.1 Promoting Digital Literacy**

The study can contribute to the promotion of digital literacy among pupil teachers and their students which is important for effective contribution in the digital economy.

##### **3.2 Supporting National Cyber Security Initiative**

The study can support National Cyber security initiatives that aim to promote cyber security awareness and education among educator and students.

### 3.3 Enhancing Online Safety

By enhancing cyber security awareness and knowledge among pupil teachers, the study can contribute to the creation of safer online environment for students and educators.

#### Review of Related Literature

**Moses Moyo, Osman Sadeck, Nyarai Tunjera, Agnes Chigona (2022)** conducted a research on 'Investigating Cyber Security Awareness Among Preservice Teachers during the COVID - 19 pandemic'. The purpose of the study was to gain an insight into CSA among preservice teachers who had been using digital technologies to support learning during the COVID - 19 pandemic'. The finding concludes that Preservice Teachers were limited in their awareness on cyber security threats and risks likely to affect their use of various digital technologies for remote learning.

**Osman Sirajeldeen Ahmed (2021)** conducted survey of teachers awareness to develop student cyber security. It is a case study. The study concluded that there was a statistical significant relationship between specialization and teacher awareness of cyber security for their student.

**Dr. Menka Chaudhary ( 2020)** conducted a survey to understand **the cyber crime awareness among higher education students from Haryana** with respect to various demographical variables which concluded that there is average cyber crime awareness among the college students from Haryana state. The result revealed that cyber crime awareness is affected by streams.

**Baris Sezer, Ramazan Yilmaz and Fatma Gizem Karaoglan Yilmaz(2015)** conducted a research on **Cyber Bullying and Teachers' Awareness**. The purpose of this study is to determine the awareness levels of teachers with regards to cyber bullying. The findings of the study reveal that the teachers in sample group of the study have an average level of awareness on cyber bullying.

#### Objectives of the Study

1. To find out the level of awareness on cyber security among pupil teachers studying in self - finance B.Ed. colleges of Meerut District.
2. To compare the level of awareness on cyber security among male and female pupil teachers studying in Self - finance B.Ed. colleges in Meerut District.
3. To compare the level of awareness on cyber security among pupil teachers who graduated in computer science/ information technology and those who graduated in other subjects.

#### Hypotheses of the Study

1. There is no significant difference in the level of awareness on cyber security among male and female pupil teachers studying in self - finance B.Ed. colleges in Meerut District.
2. There is no significant difference in the level of awareness on cyber security among pupil teachers who graduated in computer science/information technology and those who graduated in other subjects.

**Delimitation of the Study**

The study is delimited to the pupil teachers studying in self finance B.Ed. colleges in Meerut district affiliated to Ch. Charan Singh University, Meerut.

**Methodology**

**Type of Research** - It is a descriptive survey research.

**Nature of the Study** - The nature of this study is quantitative.

**Population** - The population of this study was all the pupil teachers studying in self- finance B.Ed. colleges in Meerut District.

**Sample** - This study was conducted on a sample size of 100 pupil teachers, randomly selected from different Self- finance B.Ed. colleges of Meerut District.

**Tool - Cyber Security Awareness Questionnaire** developed by the researcher was used as a tool for data collection. The main five dimensions of the tool were **password hacking, Fake advertisements, malicious protection, computer viruses, identity theft.**

**Statistical Techniques Used**

Researcher used inferential statistics to analyze the data in this study. The following statistical technique were used **Mean, Standard Deviation, t-Test.**

**Findings**

**TABLE NO – 1**

**Table showing Mean, SD, and t- Test of Awareness on Cyber Security among Pupil Teachers on the basis of gender.**

S. N.	Variable	N	Mean	SD	t – Value	Remark
1.	Female	50	63.7	10.39	1.07	Not Significant
2.	Male	50	61.82	7.12		

From the above table, it is evident that the calculated ‘t’ value for gender is 1.07 which is smaller than the tabulated value with degree of freedom 98 at .05 level of significance. Hence , null hypothesis is accepted.

It concludes that there is no significant difference in the level of awareness on cyber security among male and female pupil teachers.

**TABLE NO – 2**

**Table showing Mean, SD and t- value of Awareness on Cyber Security among Pupil Teachers on the basis of their graduation subjects.**

S. N.	Variable	N	Mean	SD	t – Value	Remark
1.	Graduated in Computer Science/I. T.	50	67.72	11.32	1.99	Significant
2.	Graduated in Other Subjects	50	64	7.94		

From the above table it is evident that the calculated 't' value graduation subjects of pupil teachers is **1.99** which is greater than the tabulated value with degree of freedom 98 at .05 level of significance. Hence , null hypothesis is rejected.

It concludes that there is a significant difference in the level of awareness on cyber security among pupil teachers who graduated in computer science/information technology and who graduated in other subjects.

The pupil teachers who graduated in computer science/information technology have higher level of awareness on cyber security than the pupil teachers who graduated in other subjects.

### **Conclusion :**

The present study aimed to investigate the Awareness of cyber security among Pupil teachers with a focus on gender and graduation subjects. The findings of the study revealed that male and female teachers have an equal level of awareness about **cyber** security which contradicts the common stereotype that males are more techno experts than females. However, the study also found that the pupil teachers who graduated in computer science/ information technology have a significantly higher level of awareness about cyber security compared to those who graduated in other subjects. This finding highlights the importance of specialized education and training in computer science and information technology in enhancing cyber security awareness.

In conclusion, this study contributes to the existing body of literature on cyber security awareness among educators. The findings of the study provide valuable insights into the factors that influence cyber security awareness among pupil teachers. By addressing the gaps in cyber security awareness, educational institutions can play a crucial role in promoting a safer and more secure online environment for students.

Recommendations for future studies include exploring the impact of cyber security awareness on teaching practices, examining the role of school administrators in promoting cyber security awareness and investigating the effectiveness of different training programs in enhancing cyber security awareness among pupil teachers.

### **Educational Implications**

- Educational institutions should integrated cyber security education into the curriculum of all subjects, not just computer science and information technology .
- Educational institutions should provide specialized training and education to pupil teachers to enhance their cyber security awareness.
- Educational institutions should develop a comprehensive cyber security curriculum that covers topics such as online safety, data protection and cyber threats.
- Educational institutions should promote digital literacy among students and educators including the safe and responsible use of technology.
- Educational institutions should collaborate with cyber security experts to provide training and education on cyber security best practices.
- Educational institutions should conduct regular cyber security awareness programs for students and educators to stay updated on the latest cyber threats and best practices.

**References :**

1. Moyo, M., Sadeck, O., Tunjera, N. Chigona, A.(2022). Investigating Cyber Security Awareness Among Preservice Teachers During the COVID - 19 Pandemic. In: Themistocleous, M., Papadaki, M.(eds) Information Systems.EMCIS 2021. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 437. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-95947-0\\_38](https://doi.org/10.1007/978-3-030-95947-0_38)
2. Ahmed, O. S., Nasef, S. A., Rawashdeh, Alea, Z. A. & Eltahai, M.E., (2021), Teachers' awareness to develop Student Cyber Security:A Case Study, *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*. Vol - 12 No - 10(2021), 5148-5156
3. Chaudhary, Menka(2020), Cyber Crime Awareness among Higher Education Students from Haryana with respect to various demographical variables - *Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17(7), ISSN 1567 - 214 x.
4. Sezer, B, Yilmaz, R. And Karaoglan Yilmaz, F.G. (2015), "Cyber Bullying and Teachers' awareness", Vol.25 No. 4, pp. 674-687. <https://doi.org/10.1108/intR-01-2014-0023>

## EMPOWERING TEACHERS FOR TECHNOLOGY INTEGRATION: CHALLENGES AND EFFECTIVE STRATEGIES

\*Sandip Das  
\*\*Dr. Sanjay Singh Yadav

### ABSTRACT

*In today's educational landscape, technology is more important, providing several opportunities for enhancing learning and instruction. However, successfully incorporating technology into the classroom raises considerable challenges, particularly for teachers. This study tries to identify and analyse the major challenges faced by teachers in the integration of technology into their teaching practices. Teachers face a variety of challenges including inadequate professional development, hesitation to embrace change, limited access to technology and infrastructure, time constraints in planning, and the need for pedagogical transformation. The study also explores effective strategies to empower teachers in overcoming these challenges. The findings indicate that overcoming barriers to technology adoption requires empowering teachers through continuous professional development, including them in decision-making processes, providing adequate collaborative time, and facilitating pedagogical transformation. Ultimately, the effectiveness of technology-driven reforms in education depends on recognizing the pivotal role of teachers and equipping them with the necessary skills, resources, and support. Addressing these challenges and implementing effective strategies will allow us to foster a more dynamic and effective learning environment that uses technology to enhance academic outcomes for all students.*

**Keywords:** *Technology integration, Challenges, Professional development, Digital Tools*

### Introduction :

Almost every aspect of contemporary life has been altered by technology, and education is no different. Classrooms around the world are progressively incorporating digital tools, platforms, and resources to improve the experience of teaching and learning. Technology in education has numerous potential benefits, ranging from online resources and interactive software to artificial intelligence-driven applications and virtual classrooms (Buck, 2023). However, there are still various types of barriers that hinder the successful integration of technology. Educators often encounter significant barriers, including inadequate training, disparities in access to technology, hesitation to embrace change, and the pressures of standardized curricula (Ertmer et al., 2012). At the core of this transformation are teachers, who must modify their teaching strategies, enhance their skill sets, and cultivate an environment that embraces technology for their students. Despite these critical responsibilities, many teachers face obstacles when trying to incorporate technology into their classrooms. Insufficient professional development often leaves them feeling unprepared to effectively use new digital tools, which can result in a return to traditional teaching practices (Sabourianzadeh & Ahmadi, 2023). Moreover, teachers frequently encounter inertia in adopting new approaches—both from within themselves and from colleagues and administrators—which can further impede the adoption of innovative practices (Sánchez & Gutiérrez-Esteban, 2023). Lack of appropriate, sustained support for teachers to develop confidence in using digital technology before classroom

---

\*Research Scholar, Department of Education, University of Lucknow, Lucknow E.Mail:- sandipdasphdlu@gmail.com, Mob.No. 8478044906

\*\*Assistant Professor, Department of Education, University of Lucknow, Lucknow, E.Mail:- drsanjaysingh1ko@gmail.com, Mob.No.8090233290

implementation is a major obstacle to effective technology integration in the classroom (Hennessy et al., 2022). The central argument is that while technology holds significant potential for enhancing education, its effective integration depends on the active involvement and support of teachers. Therefore, adequately preparing and equipping teachers to navigate technological changes is vital for the successful implementation of technology-driven educational reforms. By addressing the challenges of technology integration, an environment can be established where learning is enhanced by technology and teachers are empowered to craft a more engaging and dynamic classroom experience.

## **Technology Integration in Education: An Overview**

The integration of technology in education in India has experienced remarkable changes in recent decades, shifting from isolated computer labs to the widespread use of digital tools across all grade levels and disciplines. This incorporation of technology offers students an engaging learning experience, helping them stay interested in their studies without distraction. The use of projectors, computers, and other advanced technological resources can transform the classroom into a dynamic and enjoyable environment for students (Haleem et al., 2022). Additionally, technology plays a pivotal role in fostering essential 21st-century skills and preparing students for future challenges. Collaboration and communication tools facilitate seamless interaction among students and with educators, cultivating teamwork and effective communication abilities that are crucial in the modern workforce (Kalyani, 2024). However, integrating technology in India requires more than just providing access to devices and software. True integration requires that technology be seamlessly incorporated into the instructional process, supporting and enhancing pedagogical goals. This often necessitates a transformation from traditional teaching approaches to digital classrooms, where technology acts as a catalyst for inquiry, collaboration, and creativity (Budhia & Behera, 2023). For example, project-based learning facilitated by digital tools can promote problem-solving and critical thinking skills among students.

The National Education Policy 2020 (NEP 2020) recognizes these needs and emphasizes of integrating technology across all levels of education. The policy stresses that technology-integrated learning is vital for enhancing educational outcomes, asserting that online and digital education can effectively address equity concerns (Ministry of Human Resource Development, Government of India, 2020). Additionally, it promotes blended learning and the utilization of e-learning platforms like DIKSHA and SWAYAM to enhance accessibility and engagement in education. However, the integration of technology in education has been inconsistent throughout India, with varying degrees of adoption across different regions and institutions. While some schools, in particular those in urban areas, have embraced these changes and adopted innovative practices, many rural and under-resourced schools struggle with implementation. Challenges include technical difficulties, inadequate infrastructure, limited access to high-speed internet, and a lack of trained educators (Battur, 2024). The NEP acknowledges these disparities and advocates for the construction of robust digital infrastructure as well as ongoing professional development for educators for ensuring efficient use of technology. This situation emphasizes the importance of understanding the factors that impact technology integration, particularly the essential role of teachers. Studies show that meaningful professional development and continuous support are vital for equipping teachers to tackle these challenges and incorporate technology in their instructional practices (Endona & Buquia, 2024).



## Significance of the Study

This study may give considerable insight into the challenges that teachers experience while integrating technology and suggests effective ways to empower them. Effective integration of technology can improve student outcomes, instructional methods, educational policies, and the development of more creative and equitable learning environments. Furthermore, this study can assist in narrowing the digital divide by giving teachers with the tools and assistance they require, ensuring that all students, regardless of background, get the opportunity for, technology-enhanced education. It may also promote a setting in which teachers can grow professionally, allowing them to remain updated on evolving emerging technologies and modify their teaching strategies accordingly.

## Research Objectives

1. To identify and analyse the key challenges faced by teachers in the integration of technology into their teaching practices.
2. To explore effective strategies for empowering teachers in overcoming the challenges associated with technology integration in the classroom.

## Research Methodology

This research employs documentary analysis, relying on secondary data and government documents. The primary sources consist of government reports and publications, while secondary sources encompass journal articles, news articles, books, and various websites.

## Key challenges in Technology Integration

Teachers play a crucial part in the successful integration of technology in education. They need strong subject knowledge and proficiency with digital tools. Their attitudes and confidence significantly impact how technology is utilized in classroom. When teachers embrace technology, they can create engaging, student-centred learning experiences that enhance critical thinking and collaboration. Continuous professional development is essential for providing teachers with the most current tools and strategies. By supporting educators, educational institutions can amplify the benefits of technology, leading to a more effective and dynamic learning environment (Sabourianzadeh & Ahmadi, 2023).

Despite these potential advantages, teachers in India often confront severe barriers that prevent effective technology integration:

### Inadequate of Professional Development

One of the major challenges teachers encounter in integrating technology is the insufficient professional development. Many teachers report feeling unprepared to use new digital tools effectively, and without ongoing support, they may revert to traditional teaching methods. Effective professional development programs should extend beyond mere technical training, emphasizing how technology can enhance pedagogical practices (Singh, 2022). Teachers need opportunities to experiment with technology, collaborate with peers, and receive feedback on their efforts. The National Education Policy 2020 emphasizes the significance of continuous professional development, stressing that teachers must receive training to enhance their digital skills and more effectively incorporate technology into their teaching practices.

## **Hesitation to Embrace Change**

Change can be challenging, in particular for teachers who have developed their instructional methods over years or decades. Hesitation to embrace change is a common barrier to technology integration. Some teachers may be hesitant to adopt new technologies due to fears that it will disrupt their established routines or scepticism about its educational value (Akdeniz & Konakli, 2022). Teachers must participate in the decision-making process in order to overcome this reluctance, enabling them to explore and select technologies that fit their teaching goals.

### **Infrastructure and Access Issues**

Another significant challenge is the inadequate access to reliable technology and infrastructure. In many schools, especially in underfunded regions, both teachers and students may lack the necessary hardware, software, or high-speed internet connections needed for effective technology integration. Even with available resources, technical issues such as software glitches, slow internet speeds, or outdated equipment can disrupt lessons and frustrate both teachers and students. NEP 2020 underscores the need to construct a strong digital infrastructure to support technology integration in education, especially in rural and marginalized communities.

### **Time Constraints in Planning**

Teachers often cite time constraints as a major obstacle to integrating technology effectively. Learning to use new technologies, planning lessons that incorporate them, and troubleshooting technical issues can be time-consuming. With already heavy workloads, many teachers find it challenging to allocate the necessary time for effective technology integration into their teaching practices. Educational institutions and administrators may help reduce this issue by offering specific time for professional development, lesson planning, and collaboration.

### **Transformations in Pedagogy**

Successful technology integration frequently requires a transformation in pedagogical approaches. Traditional, teacher-centred methods may not adequately support the collaborative and student-centred learning that technology can facilitate. Teachers need to embrace more flexible, inquiry-based instructional strategies that encourage students to participate actively in the learning process. This transition could be challenging for those accustomed to traditional, lecture-based instruction. The NEP 2020 advocates for innovative teaching practices that leverage technology to boost engagement of student and enhance learning outcomes.

### **Effective Strategies for Empowering Teachers**

To address these challenges, it is critical to equip teachers with the necessary support, training, and resources to properly integrate technology into their classrooms. Below are several strategies to empower teachers in this process:

#### **Continuous Professional Development**

NEP 2020 emphasises the need of continuous professional development for teachers, focusing on training in innovative instructional approaches, ICT integration, and inclusive education practices. Investing in teacher training and capacity building is crucial to enhancing education quality in rural schools (Rana, 2024). Teachers should have opportunities to collaborate with colleagues, attend

workshops, and receive mentorship from experienced educators who have effectively integrated technology into their classrooms. The policy mandates that each teacher participate in at least 50 hours of CPD annually, tailored to their interests. They will receive comprehensive training in learner-centric pedagogy and learn to create high-quality online content using various teaching platforms and tools. It will focus on how the teacher can help students actively engage with the material and with one other (Ministry of Human Resource Development, Government of India, 2020).

### **Teacher Involvement in Decision-Making**

Engaging teachers in the decision-making process can effectively reduce hesitation to embrace change. When teachers acknowledge the necessity for change, they are more motivated to actively pursue its successful implementation within their classrooms and schools (Gómez-Parra & Daiss, 2022). Having a voice in choosing the technologies they will utilize and participating in the implementation process increases their investment in the outcomes. This can be further strengthened by forming technology leadership teams, where collaboration occurs among teachers, administrators, and IT staff to devise comprehensive strategies for integrating technology.

### **Improving Access to Resources**

NEP 2020 focuses on enhancing access to educational resources for all students and teachers. By developing a range of materials in multiple Indian languages, the policy aims to engage diverse audiences, including those in remote areas and individuals with disabilities. The DIKSHA platform will act as a centralized repository for learning and teaching e-content, featuring contributions from states and organizations like NCERT, CIET, CBSE, and NIOS. This approach not only bridges the gap between urban and rural education but also equips teachers with essential training through accessible professional development programs. Ultimately, NEP 2020 strives to create a more equitable educational system that empowers both students and teachers.

### **Providing Time for Planning and Collaboration**

To address time constraints, dedicated time should be allocated for teachers to engage in planning, experimentation, and collaboration. NEP 2020 encourages teachers to share best practices and work together to ensure all students are learning effectively. To reduce the significant time teachers currently spend on non-teaching activities, they will no longer be obligated to engage in activities unrelated to their educational responsibilities. This shift will enable teachers to focus entirely on their teaching duties.

### **Facilitating Pedagogical Transformation**

Facilitating the necessary pedagogical transformation for teachers involves providing both training and support. Access to resources and professional learning communities focused on student-centred instructional practices should be made available. Furthermore, administrators should promote experimentation and innovation in the classroom, allowing teachers the flexibility to try new approaches and learn from their experiences.

### **Conclusion**

Technology integration in education offers immense potential for enhancing teaching and learning, but its success largely depends on teachers. While there are several challenges to effective technology

integration, many of these obstacles can be overcome with the right support, resources, and professional development. Teachers must be empowered to embrace new technologies and adapt their pedagogical practices to meet the demands of 21st-century learners. By addressing issues like inadequate professional development, hesitation to embrace change, and inadequate infrastructure, educational institutions and policymakers can foster an environment where technology is seamlessly integrated into the learning and teaching process. Ultimately, effective technology integration hinges on recognizing the crucial role of teachers and equipping them with the necessary tools, training, and support to thrive in a digital age.

## References

- Akdeniz, R. K., & Konakli, T. (2022). The emergence, reasons and results of resistance to change in teachers. *International Journal on Lifelong Education and Leadership*, 8(1), 49–67. <https://doi.org/10.25233/ijlel.1107137>
- Batur, A. (2024). National Education Policy 2020 - Challenges and Opportunities on the Educational System. In *NEP- 2020: Challenges and opportunities* (1st ed., pp. 29–42). Bhumi Publishing. <https://www.bhumipublishing.com/wp-content/uploads/2024/03/NEP-2020-Challenges-and-Opportunities-1.pdf>
- Buck, L. (2023). How Technology in Education is Revolutionizing the Learning Experience? - FutureEnTech. *FutureEnTech*. <https://futureentech.com/technology-education-revolutionizing-learning/>
- Budhia, N., & Behera, S. (2023). Challenges and opportunities of digital education in India. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 45(3), 1–7. <https://doi.org/10.9734/ajess/2023/v45i3982>
- Endona, J. M. E., & Buquia, W. A. (2024). Technological Difficulties Encountered by Private School Teachers in the Implementation of Blended Learning. *International Multidisciplinary Journal of Research for Innovation, Sustainability, and Excellence (IMJRIS)*, 1(6), 38–56. <https://risejournals.org/index.php/imjrise/article/view/455>
- Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, 59(2), 423–435. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.02.001>
- Gómez-Parra, M.-E., & Daiss, B. (2022). The Concept of Change and the Teachers' Role on the Implementing Technological Transformation at School. In *Educational Theory in the 21st Century* (pp. 79–97). Palgrave Macmillan, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-16-9640-4\\_4](https://doi.org/10.1007/978-981-16-9640-4_4)
- Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M. A., & Suman, R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. *Sustainable Operations and Computers*, 3, 275–285. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.05.004>
- Hennessy, S., D'Angelo, S., McIntyre, N., Koomar, S., Kreimeia, A., Cao, L., Brugha, M., & Zubairi, A. (2022). Technology Use for Teacher Professional Development in Low- and Middle-Income Countries: A systematic review. *Computers and Education Open*, 3, 100080. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100080>
- Kalyani, L. K. (2024). The role of Technology in Education: Enhancing learning outcomes and 21st century skills. *International Journal of Scientific Research in Modern Science and Technology*, 3(4), 05–10. <https://doi.org/10.59828/ijrmst.v3i4.199>
- Ministry of Human Resource Development, Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. [https://www.education.gov.in/sites/upload\\_files/mhrd/files/NEP\\_Final\\_English\\_0.pdf](https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf)
- Rana, S. (2024). Exploring the Impact of NEP 2020 on Rural Education: Challenges and Opportunities. *International Journal for Research Trends and Innovation*, 9(5), 412–416.
- Sabourianzadeh, N., & Ahmadi, M. (2023). From Anxious to Assured: A Professional Development Program Unraveling the Transformative Power of Technology Integration for Pre-Service and In-Service EFL Teachers. *Applied Research on English Language*, 12(4), 41–70. <https://doi.org/10.22108/are.2024.139453.2175>

- Sánchez, V. V., & Gutiérrez-Esteban, P. (2023). Challenges and enablers in the advancement of educational innovation. The forces at work in the transformation of education. *Teaching and Teacher Education*, 135, 104359. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104359>
- Singh, R. (2022). The Role of Technology in Education. In शिक्षा में प्रौद्योगिकी का योगदान Social Research Foundation. <http://www.socialresearchfoundation.com/new/publish-book.php?editID=6232>

**“यू0पी0 बोर्ड एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र और छात्राओं की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन”**

**\*प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा**

**\*\*सोनु**

**शोध सार**

किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ पर शिक्षा का व्यापक रूप से प्रसार हो। प्रत्येक नागरिक चाहे वह बालक हो या बालिका, शहरी हो या ग्रामीण सभी को शिक्षा के अवसर सुलभ हो। विद्यालय को भविष्य का निर्माता कहा जाता है। छात्रों में अपने वातावरण के साथ जितना अच्छा समायोजन करने की क्षमता होगी तो इस से छात्र एवं समाज दोनों लाभान्वित होंगे। आज छात्रों की सबसे बड़ी समस्या अपने विद्यालय एवं मित्रों में सामंजस्य स्थापित करने की है। छात्र विद्यालय में अपने अध्यापकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं।

**मुख्य शब्द:** समायोजन क्षमता

एक सतत् प्रक्रिया, जिसमें एक व्यक्ति अपने और अपने पर्यावरण के बीच अधिक से अधिक सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध पैदा करने के लिए अपने व्यवहार को बदलता है, समायोजन कहलाता है।

**गेट्स और जारसिल्ड**

**अध्ययन के उद्देश्य : –**

1. माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

**शोध की परिकल्पना :-**

1. माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर नहीं है।

**परिसीमन :-**

प्रस्तुत शोध अध्ययन का परिसीमन निम्न प्रकार है—

1. प्रस्तुत अध्ययन यू0पी0 बोर्ड तथा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के सरकारी एवं पब्लिक स्कूलों तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन केवल बुलन्दशहर जनपद के माध्यमिक विद्यालयों तक सीमित है।
3. प्रस्तुत लघु शोध कार्य केवल कक्षा 10 के छात्र एवं छात्राओं तक सीमित है।

**शोध विधि :-**

शोध विधि के माध्यम से शोधकर्ता को शोध समस्या चयन से लेकर निष्कर्ष तक की क्रियाओं को पहचानना होता है तथा इन अनुसंधान की क्रियाओं को वैज्ञानिक ढंग से नियोजित करना होता है। वर्तमान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

\*प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग मेरठ कॉलेज, मेरठ मो0नं0-9761457688 ई.मेल: [meenakshims667@gmail.com](mailto:meenakshims667@gmail.com)

\*लघु शोध छात्र शिक्षाशास्त्र विभाग मेरठ कॉलेज, मेरठ मो0नं0-9720091364

न्यादर्श :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सरल यादृच्छिक चयन विधि के अन्तर्गत लॉटरी विधि द्वारा कुल 100 विद्यार्थियों, जिनमें 50 छात्र एवं 50 छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है। जिनमें से 25 छात्र एवं 25 छात्रा यू0पी0 बोर्ड तथा 25 छात्र एवं 25 छात्रा सी0बी0एस0 ई0 बोर्ड के सरकारी एवं पब्लिक स्कूलों के माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत हैं।

उपकरण :-

शोधकर्ता की अपने शोध अध्ययन के लिए शोध के अनुरूप प्रयुक्त उपकरणों के चुनाव पर ही शोध अध्ययन की सफलता निर्भर करती है। शोध पत्र हेतु आँकड़े एकत्र करने के लिए निम्नलिखित प्रमापीकृत शोध उपकरण का प्रयोग किया गया है—ए0के0पी0 सिन्हा तथा आर0पी0 सिंह द्वारा निर्मित मापनी Adjustment Inventory For School Students (Hindi Version)

सांख्यिकीय विश्लेषण:-

प्रयुक्त शोध उपकरणों से प्राप्त आँकड़ों का संकलन करने के पश्चात् निम्नलिखित सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग किया गया— माध्य, मानक विचलन, टी—परीक्षण। टी—परीक्षण को वर्तमान अध्ययन के आँकड़ों को समझने के लिए लागू किया गया है।

तालिका नं0-1  
छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता की तुलना

क्र 0 सं 0	समूह	न्यादर्श N	मध्यमान M	मानक विचलन (SD)	D	$\sigma D$	t-value	सार्थकता स्तर
1	छात्र	50	33.04	3.87	5.34	1.18	4.52	0.5 स्तर तथा 0.1 स्तर
2	छात्राएँ	50	27.7	6.48				

$$\begin{aligned} \text{स्वतन्त्रता स्तर (df)} &= N_1+N_2-2 \\ &= 50+50-2=100-2 \\ &= 98 \end{aligned}$$

तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दोनों समूहों के मध्य गणनात्मक टी का मान 4.52 है। df=98 पर तालिका मान पर सार्थकता स्तर 0.05 पर 1.98 तथा 0.01 स्तर पर तालिका मान 2.63 अस्वीकृत है। टी का मान दोनों स्तरों पर अधिक है। अतः परिकल्पना 1 अस्वीकार की जाती है। माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर है। अतः माध्यमिक स्तर पर छात्राओं की अपेक्षा छात्रों की समायोजन क्षमता अधिक है।

तालिका नं0-2  
छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता की तुलना

क्र0 सं0	समूह	न्यादर्श N	मध्यमान M	मानक विचलन (SD)	D	$\sigma D$	t-value	सार्थकता स्तर
1	छात्र	50	10.8	3.26	1.68	0.63	2.66	0.5 स्तर तथा 0.1 स्तर
2	छात्राएँ	50	9.12	3.07				

df=98 पर तालिका-2 से ज्ञात होता है कि दोनों समूहों के मध्य गणनात्मक टी का मान 2.66 है। df=98 पर तालिका का मान सार्थकता स्तर 0.05 पर 1.98 तथा 0.01 स्तर पर तालिका का मान 2.63 अस्वीकृत है। टी का मान दोनों स्तरों पर अधिक है। अतः परिकल्पना 2 अस्वीकार की जाती

है। अतः कहा जा सकता है। कि कक्षा 10 की छात्राओं की तुलना में कक्षा 10 के छात्रों की शैक्षिक समायोजन क्षमता अधिक है।

परिणाम

1. माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर है।
2. माध्यमिक स्तर पर छात्र एवं छात्राओं की शैक्षिक समायोजन क्षमता में सार्थक अन्तर है।

**सुझाव :-**

प्रस्तुत शोध जनपद बुलन्दशहर में यू0पी0 बोर्ड तथा सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं तक सीमित है। इसे स्नातक स्तर के छात्राओं एवं छात्रों तथा विभिन्न विद्यालयों में वृहद स्तर पर किया जा सकता है।



## वर्तमान शिक्षा में आदर्शवादी विचारों की प्रासंगिकता

\* श्रीमती वर्धा शर्मा

\*\* डॉ० (श्रीमती) बीना अग्रवाल

### शोध सार

शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शिक्षार्थी का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक आदि सभी पक्षों का विकास किया जाता है, परंतु वर्तमान में शिक्षा के स्वरूप को ही बदल दिया गया है। इस आधुनिकीकरण के युग में शिक्षार्थी के केवल शारीरिक और मानसिक (तकनीक) पक्ष के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शिक्षार्थियों में मूल्य, आदर्श, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का पतन हो रहा है, जिसका प्रभाव शिक्षार्थी के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन पर पड़ता है। अतः इस शोध पत्र के अंतर्गत शोधार्थी द्वारा इस गंभीर समस्या को इंगित करते हुए मूल्यों पर आधारित आदर्शवाद के सिद्धांत, विशेषताओं एवं शिक्षा की अवधारणा का, वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है।

### प्रस्तावना—

शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के “शिक्ष्” धातु से हुई है, जिसका अर्थ है ‘सीखना और सिखाना’। इस अर्थ में यदि हम देखें, तो शिक्षा में वह सब कुछ निहित है, जो हम समाज में रहकर सीखते हैं। समाज में रहकर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, उसी के परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों से ऊँचा उठता है और सभ्य एवं सामाजिक प्राणी बनने की इच्छा रखता है।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री अरस्तु के अनुसार “शिक्षा पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊँचा उठाने का कार्य करती है।”<sup>1</sup>

शिक्षा समाज में समाज के लिए तथा समाज द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है। यह एक गतिशील एवं उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, जो समाज में परिवर्तन लाने की चेष्टा रखती है। इसका उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। अर्थात् बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास करना है।

शिक्षा के इन सभी पक्षों के विकास में से यदि कोई भी एक पक्ष पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, तो शिक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। बालक के इन सभी पक्षों के विकास में आदर्शवादी विचारधारा की विशेष आवश्यकता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य जीवन पूर्णता को तभी प्राप्त कर सकता है, जब वह शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों का पालन करे। आदर्शवादी विचार धारा का उद्देश्य बालक के अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास करना है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक आदि सभी उद्देश्य निहित हैं।

### अध्ययन की आवश्यकता—

शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सदैव शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास करना ही रहा है। सर्वांगीण विकास के अन्तर्गत शिक्षार्थी के सभी (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि) पक्षों पर ध्यान देना शिक्षा का प्रथम कर्तव्य माना गया है। यदि हम वर्तमान शिक्षा की बात करें तो यह A.I. (Artificial Intelligence) का युग है और शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी को इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना ही, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य हो गया है, इस प्रतिस्पर्धा की तैयारी में शिक्षार्थी के शारीरिक तथा मानसिक पक्षों पर तो भरपूर जोर दिया जा रहा है परन्तु अन्य पक्षों की अवहेलना

\*एम०एस—सी० (वनस्पति शास्त्र), एम०एड०, नेट (शिक्षाशास्त्र), E:Mail- vardha.sharma81@gmail.com, मो०नं०—8218377489,

\*\*एम०ए० (हिन्दी) पी—एच०डी० (हिन्दी), एम०एड०, E:mail- Beenagoyal999@gmail.com, मो०नं०—9412350101, 7017568337

की जा रही है। इस तकनीकी युग में हमें हर पल यह महसूस होता है कि आज मानव एक मशीन के जैसा ही व्यवहार करने लगा है। यह तकनीकी शिक्षा, शिक्षार्थी के आध्यात्मिक, सामाजिक तथा सांवेगिक पक्षों पर ध्यान देने में सार्थक भूमिका नहीं निभा पा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानवीय मूल्यों का धीरे-धीरे पतन ही दिखाई पड़ रहा है। आज हम मानव के अन्दर असंतोष, हिंसक प्रवृत्ति, स्वार्थ, बड़ों का अनादर, मानसिक अस्थिरता, प्रतिस्पर्धा में किसी भी प्रकार जीतने की प्रवृत्ति जैसे गुणों को विकसित होते देख सकते हैं। फलस्वरूप मानवीय मूल्यों का संकट गहराता जा रहा है, जिसका वर्तमान उदाहरण समाज में Old age home की संख्या का बढ़ना, शिक्षार्थी का किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने तथा अपने से बड़ों के डाँटे जाने पर आत्महत्या जैसा कदम उठाना, जायदाद के लिए आपसी झगड़े या हत्या कर देना, बलात्कार, मात्र कुछ कहासुनी होने पर दूसरे की हत्या तक कर देना, आध्यात्मिक मूल्यों पर अविश्वास, तलाक के केसों का बढ़ना आदि उदाहरण आए दिन देखने तथा सुनने को मिल जाते हैं।

यह सभी उदाहरण मानवीय मूल्यों के गिरावट तथा पतन को दर्शाते हैं। यह एक गम्भीर विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि शिक्षार्थी समाज का ही हिस्सा है। यदि किसी शिक्षार्थी में व्यक्तिगत मूल्यों का विकास ही नहीं हो पायेगा, तो हम यह कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वह शिक्षार्थी एक अच्छा नागरिक बन सकेगा और स्वयं के अन्दर सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकेगा। ऐसे मानवीय मूल्यों से, आदर्शों से विहीन नागरिकों के समाज वाला देश कभी भी उत्थान की ओर अग्रसर नहीं हो सकेगा।

अतः इस विचारणीय समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि देश के प्रत्येक शिक्षार्थी के अन्दर मानवीय मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए। अतः पाश्चात्य दर्शन के आदर्शवाद में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के अन्दर मूल्यों का विकास करना ही है। आदर्शवादी विचारधारा शिक्षार्थी के भीतर शिक्षक के माध्यम से सभी प्रकार के मूल्यों को विकसित करने पर जोर देती है।

अतः इस आदर्शवादी विचारधारा एवं शिक्षा की वर्तमान शिक्षा में सबसे अधिक आवश्यकता एवं उपयोगिता है।

**अध्ययन का क्षेत्र**—प्राचीनतम पाश्चात्य दर्शन पर आधारित आदर्शवाद के शैक्षिक विचारों का वर्णन किया गया है।

**अध्ययन की विधि**—जॉन वेस्ट ने शोध की विधियों को तीन भागों में बाँटा है 1. ऐतिहासिक विधि, 2. वर्णनात्मक विधि, 3. प्रयोगात्मक विधि

इस अध्ययन में शोध की वर्णनात्मक विधि को अपनाया गया है।

## आदर्शवाद के शैक्षिक विचार

### शिक्षा का अर्थ—

आदर्शवाद के जनक प्लेटो थे। आदर्शवादी विचारकों ने शिक्षा का अभिप्राय मनुष्य का पूर्ण मानव के रूप में विकास करना बताया है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि "शिक्षा का अभिप्राय है—बालक को आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण करना।"<sup>2</sup>

आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षा वह है, जो सिर्फ बालक के विकास तक ही सीमित नहीं रहती, बालक को विकसित करके समाज का विकास करना चाहती है और आवश्यकता पड़ने पर समाज सुधारने का भी प्रयास करती है। अतः आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा से आशय ज्ञान, अनुभव, सामाजिक तैयारी, मानवता से परिपूर्ण गुणों का विकास, समायोजन, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करना तथा ईश्वर के गुणों की प्राप्ति कराना है।

## आदर्शवाद के प्रारूप—

1. आत्मनिष्ठ आदर्शवाद
2. प्रपंचवाद आदर्शवाद
3. वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद
4. नैतिक आदर्शवाद

## वर्तमान शिक्षा में आदर्शवादी विचारों की प्रासंगिकता—

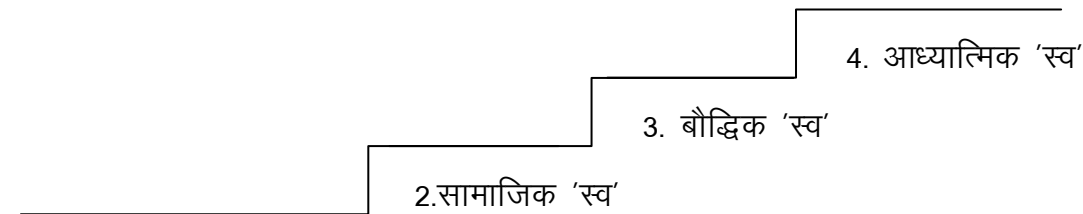
वर्तमान शिक्षा शिक्षार्थियों को तकनीकी ज्ञान देने की ओर तटस्थ है, जिससे शिक्षार्थी इस संसार के किसी भी कोने में जाकर स्वयं को समायोजित कर सकें और खुद को पिछड़ा हुआ न समझें। परन्तु मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप आदि से जुड़ी तकनीकी शिक्षा देने की होड़ में हम शिक्षार्थी को आध्यात्मिक ज्ञान का हस्तान्तरण शिक्षा के माध्यम से कराना भूलते ही जा रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षा के अभाव में शिक्षार्थी चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांवेगिक रूप से पूर्णतः विकसित नहीं हो पा रहा है।

अतः वर्तमान शिक्षा के अन्तर्गत आदर्शवादी शिक्षा का सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, जिससे शिक्षार्थी आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ सकें और स्वयं को पूर्णता प्रदान कर सकें।

## आदर्शवाद व शिक्षा के उद्देश्य—

### 1. आत्मानुभूति का विकास—

आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च कार्य यह है कि वह मनुष्य को इतना सक्षम बनाए कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने तथा उसकी अनुभूति कर सके। इस आत्म अनुभूति के प्रमुख रूप से चार सोपान होते हैं—



### 1. शारीरिक व जैविकीय 'स्व'

(1). **शारीरिक स्व**—शारीरिक स्व आत्मानुभूति का निम्नतम सोपान है। आदर्शवादी यह मानते हैं कि आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के लिए सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य का प्राकृतिक विकास है, इसीलिए वे शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देते हैं।

(2). **सामाजिक स्व**— आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के मार्ग का दूसरा सोपान सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास का अर्थ है— मनुष्य समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करता है, क्योंकि उसकी पसंद सामाजिक स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर करती है। इस स्तर पर मनुष्य अपने प्राकृतिक व्यवहार पर नियंत्रण करना सीख जाता है। इसे ही समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक विकास कहते हैं।

(3). **बौद्धिक स्व**— आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का तीसरा सोपान बौद्धिक विकास है। यह वह स्थिति है, जब मनुष्य का व्यवहार राज्य के नियमों से नियंत्रित न होकर उसकी अपनी बुद्धि एवं विवेक द्वारा नियंत्रित होता है। इनका मानना है कि बिना बुद्धि के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत्यम, शिवम, सुन्दरम की प्राप्ति नहीं हो सकती।

(4). **आध्यात्मिक स्व**— यह आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति का अन्तिम सोपान है। इसके अन्तर्गत मनुष्य प्राकृतिक एवं सामाजिक विकास से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि को नियंत्रित करने लगता है और वह

धीरे-धीरे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने लगता है। ऐसा मनुष्य भी चिर सत्य, चिर शिव, चिर सौन्दर्य की खोज करके आत्मा-परमात्मा को जान लेता है।

## 2. आध्यात्मिक मूल्यों का विकास—

आदर्शवादी विचारधारा मनुष्य को एक नैतिक प्राणी के रूप में अवलोकित करती है। वह शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानती है। वह सत्यम, शिवम, सुंदरम के मूल्यों का विकास करते हुए यह बताती है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक विकास करना है।

## 3. बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन—

आदर्शवादी बोगोस्लोवस्की के अनुसार "हमारा उद्देश्य छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वह संपन्न तथा सारयुक्त जीवन बिता सकें, सर्वांगीण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, सुखी रहने के लिए उल्लास का उपभोग कर सकें, यदि तकलीफ आए तो गरिमा एवं लाभ के साथ उनका सामना कर सकें, तथा इस उच्च जीवन को जीने में दूसरे लोगों की सहायता कर सकें।"<sup>3</sup>

## 4. अनेकता में एकता के दर्शन—

बालक के अंदर यह समझ विकसित करना कि संसार का संचालन करने वाली एक परम सत्ता है जो ईश्वर के नाम से जानी जाती है। एक ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान कराना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए।

## 5. सभ्यता एवं संस्कृति का विकास—

आदर्शवाद व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्त्व देता है, इसी कारण वह शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति का विकास करना मानते हैं।

## 6. वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्त्व—

आदर्शवाद के अनुसार "विचार" सत्य, वास्तविक एवं अपरिवर्तनशील है। यह संसार मनुष्य के विचारों में ही निहित होता है। आदर्शवाद यह मानता है कि यह जगत यंत्रवत नहीं है, क्योंकि इस जगत में विद्यमान वस्तुओं का जन्म मानसिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही होता है। इनका विचार है कि यह विश्व विचार के समान है, यंत्रवत नहीं।

## 7. जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्त्व—

आदर्शवादी मनुष्य का स्थान ईश्वर से थोड़ा ही नीचा मानते हैं। वह जड़ प्रकृति से अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य बुद्धिपूर्ण तथा विवेकपूर्ण प्राणी है। बुद्धि ही मनुष्य के विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों का आधार बनाती है, जिससे मानव अपने आप को पशुवत गुणों से ऊँचा उठा लेता है।

## 8 समाज हित का उद्देश्य—

आदर्शवाद जब शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करता है, तो व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है और व्यक्तित्व विकास में सामाजिक हित अंतरनिहित होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करना। सिर्फ संस्कृति का संप्रेषण मात्र करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि संप्रेषण मात्र से संस्कृति का स्थानांतरण होना संभव नहीं है।

## आदर्शवादी शैक्षिक उद्देश्य की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता—

आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति कराना है, जिसके लिए मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों के विकास पर बल दिया है। यह शिक्षा शिक्षार्थी को भौतिक जीवन जीने एवं आध्यात्मिक पक्षों को विकसित करने का उद्देश्य रखती है, जिससे शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में संपूर्णता आ सके, यदि शिक्षार्थी में संपूर्णता एवं संतोष का

विकास होगा तो वह एक उत्कृष्ट सामाजिक प्राणी एवं देश को विभिन्न ऊँचाईयों पर पहुँचाने वाला नागरिक बन सकेगा।

### आदर्शवाद व पाठ्यक्रम—

आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति निश्चित करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र को प्रमुख और अन्य विषयों एवं क्रियाओं को दूसरा स्थान देते हैं।

ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के अनुसार मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है, इसके लिए सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की प्राप्ति आवश्यक होती है, जिसके लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में बौद्धिक क्रियाओं के लिए भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा शारीरिक क्रियाओं के लिए शारीरिक विज्ञान का, नैतिक क्रियाओं के लिए धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र तथा आध्यात्मिक शास्त्र का, वहीं कलात्मक क्रियाओं हेतु विभिन्न कलाओं तथा संगीत का समावेश किया था।<sup>4</sup>

जर्मन के आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री हरबर्ट महोदय के अनुसार "मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए चारित्रिक एवं नैतिक विकास पर बल देना चाहिए तथा पाठ्यचर्या में विषयों का चयन उसी के अनुसार किया जाना चाहिए।"<sup>5</sup> इंग्लैंड के आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री टी पी नन महोदय की दृष्टि से पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों का समावेश किया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य को मानव सभ्यता एवं संस्कृति की झलक मिल सके और जिनके द्वारा बच्चों को कुछ विशेष क्रियाओं में अनुशासित एवं प्रशिक्षित किया जा सके।<sup>6</sup>

### आदर्शवाद के पाठ्यक्रम की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता—

वर्तमान शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए पाठ्यक्रम में योग शिक्षा, खेल-कूद पर अधिक जोर दिया जा रहा है, साथ ही क्रिया-प्रधान गतिविधियों को लगभग सभी विषयों में सम्मिलित भी किया जा रहा है, जिससे शिक्षार्थियों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक पक्षों का विकास किया जा सके। वहीं यदि हम आदर्शवाद में पाठ्यक्रम पर ध्यान पर दें तो आदर्शवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शारीरिक विज्ञान, नैतिक क्रियाओं, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र तथा बौद्धिक क्रियाओं हेतु गणित, भूगोल, साहित्य, भाषा, तथा कलात्मक क्रियाओं हेतु विभिन्न कलाओं तथा संगीत का समावेश किया गया है।

उपर्युक्त सभी विषय वर्तमान शिक्षा एवं शिक्षार्थियों के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।

### शिक्षण विधियाँ—

शिक्षण विधियों के संबंध में आदर्शवादी दार्शनिक यह मानते हैं कि वह किसी भी शिक्षण विधि के अनुयायी मात्र नहीं है वरन् वह शिक्षण विधियों के निर्माता व सृजनकर्ता है। साथ ही यह विचारधारा इस बात पर भी बल देती है कि इन विधियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बालक की रुचि, योग्यता, आयु भी इनके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आदर्शवादी विधियों पर अपना आधिपत्य स्वीकार करते हैं। वह स्वयं को विधियों के दास नहीं मानते हैं। आदर्शवादी दर्शन जिन विधियों के प्रयोग की चर्चा करता है वह हैं— प्रश्न विधि, संवाद विधि, निगमन एवं आगमन विधि, वाद विवाद विधि, निर्देशन विधि, तर्क विधि, खेल विधि, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि व नाटक विधि।

### आदर्शवादी शिक्षण विधियों की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता—

प्राचीन आदर्शवादी विचारक अनेक उत्तम विधियों, प्रश्न उत्तर, वाद-विवाद, संवाद, आगमन तथा निगमन विधियों का प्रयोग करते थे। आधुनिक आदर्शवादी विचारक तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भी परिचित

है। वे शिक्षार्थी के करके सीखने और स्व अनुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। इस संदर्भ में पेस्टोलाजी के अभ्यास और आवृत्ति विधि, हरबर्ट की पंचपदीय प्रणाली और फ्रोबेल के किंडरगार्डन प्रणाली उल्लेखनीय है।

### आदर्शवाद और अनुशासन—

आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार आत्मा का स्वअनुशासित होना ही सच्चा अनुशासन है। आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो के अनुसार बच्चों को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसरित करने के लिए नैतिक आचरण आवश्यक होता है। उनका मानना है कि वास्तविक अनुशासन आंतरिक होता है, जिसमें मनुष्य अपने अंतःकरण से प्रेरणा प्राप्त करता है<sup>8</sup> साथ ही आधुनिक युग के आदर्शवादी विचारक जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने स्पष्ट किया कि दंड के भय से वास्तविक अनुशासन की प्राप्ति नहीं की जा सकती<sup>9</sup>। सच्चे अनुशासन की प्राप्ति के लिए प्रेम एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार की आवश्यकता है। इस प्रकार आदर्शवादी अनुशासन को आंतरिक भावना मानते हैं और छात्रों में इसका विकास करने के लिए विद्यालयों में उच्च पर्यावरण के निर्माण एवं विकास पर बल देते हैं।

### आदर्शवाद के अनुशासन की वर्तमान शिक्षा में प्रासंगिकता—

अनुशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो प्राचीन या वर्तमान दोनों ही शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, बदलते परिवेश में शिक्षार्थी का आत्मानुशासित होना ही उचित है, यदि शिक्षार्थी पर बल द्वारा अनुशासन थोपा जाएगा तो वह अवसाद, मानसिक अस्थिरता, शिक्षा में अरुचि, नैतिक पतन जैसी परेशानियों का सामना करेगा। अतः आदर्शवादी विचारकों ने भी आत्मानुशासन पर ही बल दिया है।

### शिक्षक और शिक्षार्थी—

आदर्शवादी विचारक शिक्षक का स्थान शिक्षण प्रक्रिया में सर्वोपरि मानते हैं। वे शिक्षकों को उस अनुपम स्थिति में रखते हैं, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया का कोई अंश नहीं रखा जा सकता।

शिक्षार्थी को आदर्शवादी जन्म से पूर्ण मानते हैं और इस पूर्णता की अनुभूति के लिए वे शिक्षार्थी हेतु कठोर आचार संहिता बनाते हैं, जिसका पालन करना आवश्यक होता है।

### वर्तमान शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी हेतु आदर्शवादी विचारों की प्रासंगिकता—

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा जगत में भ्रष्टाचार की अधिकता के परिणाम स्वरूप आदर्श शिक्षकों की कमी दिखाई पड़ती है। यदि शिक्षक ही अपने मूल्यों पर अधिक ध्यान नहीं देगा तो उसका शत प्रतिशत प्रभाव उसके शिक्षार्थी पर पड़ेगा। अतः वर्तमान शिक्षा के सार्थक परिणाम हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षक को अपने मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं आदर्शवादी शिक्षा विचारक शिक्षक को सबसे ऊँचे पद पर रखते हैं और वह शिक्षक में सभी मूल्यों जैसे नैतिक, आध्यात्मिक आदि गुणों के विकास की बात करते हैं।

वर्तमान सदी 21 वीं सदी है, अर्थात् हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, आज की शिक्षा में तकनीकी और आधुनिक मूल्यों की ही प्रधानता है, आज का शिक्षार्थी AI(Artificial intelligence) और Chat G.P.T. (Chat Generative Pre-training Transformer) जैसी सभी विधाओं में महारत प्राप्त करना चाहता है परन्तु हमारी सभ्यता तथा संस्कृति से जुड़े व्रत व उत्सवों का सही मूल्य उसे नहीं पता, उसे गीता, महाभारत, रामायण जैसे मूल्यवान, आध्यात्मिक ग्रंथों की कोई पहचान नहीं है और न ही कोई रुचि है, वह (शिक्षार्थी) केवल उन कौशलों को, उन मूल्यों को सीखना व समझना चाहता है जो उसे आर्थिक रूप में मजबूत करें। हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति के विभिन्न मूल्यों की उपेक्षा कर वह (शिक्षार्थी) स्वयं को तनाव, अलगाव, असामाजिक, पारिवारिक रिश्तों को निभाने में असक्षम, मानसिक रूप से उपेक्षित असंतुष्ट तथा शोषित महसूस करता है, ऐसे असंतुष्ट देश के भावी नागरिकों (शिक्षार्थी) से बना देश किस

प्रकार एक विकसित देश के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। अतः इस ओर चिंता प्रकट करते हुए NCERT (National Council of Education Research And Training) ने मूल्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और इस ओर निम्नलिखित प्रयास किये—

NCERT द्वारा युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय डॉपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के साथ स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। जिससे खेल-खेल में शिक्षक तथा शिक्षार्थी समय का सही सदुपयोग कर मूल्य विकसित कर सकें, साथ ही पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली पुस्तकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया और मूल्यांकन हेतु ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया जिससे शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास हो सके।<sup>7</sup> NCERT ने वर्तमान समय में 83 मूल्यों का उल्लेख किया है, जिसमें से कुछ मूल्य इस प्रकार से हैं— (1) दूसरों के सांस्कृतिक मूल्यों की सराहना (2) अस्पृश्यता विरोध (3) नागरिकता (4) दूसरों की चिन्ता (5) दूसरों का ध्यान रखना (6) सहयोग (7) सामान्य अच्छाई (8) प्रजातान्त्रिक निर्णय लेना (9) व्यक्ति की महत्ता (10) शारीरिक कार्य का सम्मान (11) साथी भावना (12) अच्छे आचरण (13) राष्ट्रीय समाकलन (14) आज्ञापालन (15) समय का सदुपयोग (16) ज्ञान की खोज (17) संयम (18) करुणा (19) सामान्य लक्ष्य (20) शिष्टाचार। इन मूल्यों के माध्यम से पाठ्यक्रम द्वारा बालकों में हो रहे मूल्यों के पतन को कम किया जा सके और उनके मानवीय मूल्यों का विकास किया जा सके।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के अन्तर्गत मूल्यों के विकास हेतु सर्वप्रथम राधाकृष्णन् आयोग (1948-49) ने मूल्य शिक्षा पर जोर दिया (NCERT-2012 पृ0-2) आदर्शवाद में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी के अन्दर मूल्यों का विकास करना है। अतः यदि बात मूल्यों की की जाये तो वहाँ आदर्शवाद का उल्लेख अनिवार्य है।

### उपसंहार—

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आदर्शवादी विचार वर्तमान शिक्षा में भी प्रासंगिक हैं। जहाँ एक ओर आदर्शवाद इस शिक्षा का अंतिम लक्ष्य शिक्षार्थियों के लिए ईश्वर की खोज करना अथवा पारलौकिक जगत या आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना मानता है, वहीं दूसरी ओर वह शिक्षार्थियों के लिए अनुशासन, नैतिकता, भाषा एवं साहित्य के ज्ञान प्राप्ति की बात करता है, क्योंकि एक उच्च समाज के निर्माण के लिए पढ़ाई करके पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक उच्च व्यक्तित्व की प्रधानता वाले सामाजिक नागरिक की भी बहुत आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल आदर्शवादियों ने दिया है तथा आदर्शवादियों द्वारा विकसित शिक्षण विधियों का प्रयोग भी किसी न किसी रूप में आज भी किया जाता है। अपनी इन विशेषताओं के कारण ही संसार में इस दर्शन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

### सन्दर्भ ग्रंथ सूची—

1. सक्सेना, डॉ० सरोज (नवीन संस्करण) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, साहित्य प्रकाशन, आगरा पृष्ठ संख्या, 01
2. सक्सेना, डॉ० सरोज (नवीन संस्करण) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, साहित्य प्रकाशन, आगरा पृष्ठ संख्या, 152
3. सक्सेना, डॉ० सरोज (नवीन संस्करण) शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, साहित्य प्रकाशन, आगरा पृष्ठ संख्या, 153

4. लाल, प्रो० रमन बिहारी (2018), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ पृष्ठ संख्या 150
5. लाल, प्रो० रमन बिहारी (2018), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ पृष्ठ संख्या 150
6. लाल, प्रो० रमन बिहारी (2018), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ पृष्ठ संख्या 150
7. [google.com/adda247/hindicurrentaffair](https://www.google.com/adda247/hindicurrentaffair)
8. लाल, प्रो० रमन बिहारी (2018), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ पृष्ठ संख्या 152
9. लाल, प्रो० रमन बिहारी (2018), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्रीय आधार, आर०लाल बुक डिपो, मेरठ पृष्ठ संख्या 152



## EMPOWERING PROSPECTIVE TEACHERS THROUGH GOVERNMENT DIGITAL PORTALS: STRATEGIES FOR INTEGRATION IN TEACHER EDUCATION

\* Subhadra Singh

\*\* Dr. Surya Narayan Gupta

### ABSTRACT

*The integration of government Digital Portals into teacher education programs is pivotal for equipping Prospective Teachers with the skills necessary for modern classrooms. Platforms such as SWAYAM, DIKSHA, and NDLI offer a range of resources, including online courses, professional development tools, and multimedia content, which foster digital literacy and enhance teaching practices. This paper explores the role of these government initiatives in empowering Prospective Teachers, focusing on their benefits, challenges, and opportunities. It also proposes a suggestive module for integrating these digital platforms into teacher education curriculums, ensuring that Prospective Teachers are adequately trained to utilize these resources effectively. The study emphasizes the need for improved infrastructure, mentorship, and collaborative efforts between institutions and government agencies to maximize the potential of these portals. By addressing these key areas, Digital Portals can help build a more inclusive, equitable, and innovative educational environment for teachers.*

**Keywords:** Government Digital Portals, Prospective Teachers, Teacher Education, SWAYAM, DIKSHA, NDLI, Digital Literacy, Professional Development, Blended Learning.

### Introduction:

The rapid strides in digital technology have profoundly impacted various facets of human endeavour, including education. Recognizing the transformative power of technology, the Indian government launched the *Digital India* initiative in 2015, aimed at strengthening the nation's digital infrastructure and improving access to technology-driven services. A cornerstone of this initiative is its focus on education, with Digital Portals playing a pivotal role in making learning accessible, inclusive, and equitable. As highlighted in the *National Education Policy 2020 (NEP 2020)*, leveraging technology in education is essential for enhancing teaching-learning outcomes and bridging the digital divide (Government of India, 2020).

The shift to digital learning gained unprecedented momentum during the COVID-19 pandemic, which forced educators and students to adapt to online platforms. Government portals such as SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds), DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing), and the National Digital Library of India (NDLI) emerged as vital tools in sustaining education during this crisis. These platforms, designed to cater to diverse stakeholders, have equipped Prospective Teachers—students undergoing teacher training programs—with essential digital competencies, enabling them to meet the demands of 21st-century classrooms.

Teacher education institutions (TEIs) are at the forefront of preparing a new generation of educators adept at using digital tools. Prospective Teachers require training not only in pedagogy but also in integrating technology into their teaching practices.

---

\*Research Scholar, Department of Education, University of Lucknow, E.Mail:- subhi4936@gmail.com, Phone: 7905814185

\*\*Assistant Professor, Department of Education, University of Lucknow, E.Mail:- vicharthegreat@gmail.com, Phone: 9305352806

Studies by Kumar and Pande (2021) and Goel and Malik (2021) highlight the need for awareness and effective utilization of government Digital Portals among teacher trainees to maximize their potential.

This paper explores the role of Government – initiated Digital Portals in preparing Prospective Teachers, identifying challenges, and proposing strategies to enhance their adoption. By equipping future educators with digital literacy and resources, these initiatives aim to create a robust and inclusive education system that aligns with global standards.

## Literature Review

Digital transformation in education aims to make learning accessible and inclusive. In India, initiatives like **Digital India** and the **National Education Policy 2020 (NEP 2020)** advocate leveraging technology to bridge the digital divide and enhance teaching-learning processes. Platforms such as **SWAYAM**, **DIKSHA**, and **NDLI** provide resources like MOOCs, e-books, and lesson plans, enabling flexible and inclusive learning (Bajpai, 2021). Studies emphasize their role in promoting interactive and blended learning models, helping Prospective Teachers adapt to evolving pedagogical methods (Philomina & Sambandamurthi, 2016; Latheef, 2018). Globally, MOOCs have proven effective in equipping educators with technological and pedagogical skills (Kennedy et al., 2016).

Awareness and usage of digital portals among Prospective Teachers remain limited. Low digital literacy, insufficient training, and disparities in ICT access hinder adoption (Goel & Malik, 2021). During the COVID-19 pandemic, educators faced challenges in transitioning to online teaching, highlighting gaps in preparedness (Kumar & Pande, 2021). ICT awareness significantly impacts teaching competency, but disparities across institutions affect its integration (Jasmine Anne Shyla, 2019; Gupta & Dharamveer, 2017).

Several barriers impede the effective use of digital portals. Poor internet connectivity, lack of devices, and inadequate technical support are major challenges (Thakur, 2014; Patna & Sinha, 2019). Gaps in regional language content further restrict accessibility, while socio-economic inequalities exacerbate the digital divide (Government of India, 2020).

Despite these challenges, digital portals offer transformative potential for teacher education by enabling personalized learning, professional development, and access to diverse resources (Mailavelan & Baskaran, 2018). Blended learning, combining traditional and digital methods, as emphasized in NEP 2020, can create holistic learning experiences. However, research gaps remain, particularly in addressing the specific needs of Prospective Teachers, regional disparities, and the long-term impact of digital training on teaching effectiveness. Addressing these gaps could enhance the effective integration of digital education in teacher training.

## Objectives

The objectives of this paper are as follows:

1. To list out various Government - initiated Digital Portals designed for Prospective Teachers.
2. To study the role of Government - initiated Digital Portals in empowering Prospective Teachers.
3. To identify the challenges associated with the awareness, accessibility, and usage of Government - initiated Digital Portals among Prospective Teachers.

4. To propose a suggestive module for integrating Government - initiated Digital Portals into teacher education programs, ensuring effective utilization and long-term impact on teaching practices.

### Keywords and Definitions


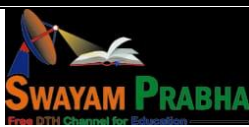




- Prospective Teachers:** Students enrolled in teacher education programs (such as B.Ed.) who are being trained to join the teaching profession. Prospective Teachers are expected to develop skills that meet the demands of diverse learners and adapt to modern pedagogical techniques.
- Digital Portal:** A digital platform (website, app, or system) that provides a one-stop solution for specific objectives, such as accessing e-resources, MOOCs, or digital repositories. Examples include SWAYAM, DIKSHA, and NDLI, initiated by the Government of India to make education equitable, accessible, and digitally empowered.

### Objective wise analysis-

#### Objective 1: To List Out Various Government - initiated Digital Portals Designed for Prospective Teachers

The Indian government has launched a range of Digital Portals aimed at transforming teacher education and empowering Prospective Teachers. These platforms are repositories of high-quality educational resources, designed to enhance accessibility and foster digital literacy. Below is a list of key portals:

**TABLE- 1**  
**Government initiated digital portals**

SNO.	LIST OF PORTALS	LOGO	OBJEVTIVE	URL
1.	SWAYAM		To provide Massive Open Online courses	<a href="https://swayam.gov.in/">https://swayam.gov.in/</a>
2.	SWAYAMPARBHA		Telecasting of educational programmes 24*7	<a href="https://www.swayamprabha.gov.in/">https://www.swayamprabha.gov.in/</a>
3.	e-PATHSHALA		National platform for school education	<a href="https://epathshala.nic.in/epathshala.php?ln=en">https://epathshala.nic.in/epathshala.php?ln=en</a>
4.	DIKSHA		Showcasing and disseminating educational e-resources	<a href="https://www.diksha.gov.in/">https://www.diksha.gov.in/</a>
5.	NDL		Digital repository of educational contents	<a href="https://ndl.iitkgp.ac.in/">https://ndl.iitkgp.ac.in/</a>
6.	FOSSEE		To spread open sourcesoftwares for education	<a href="https://fossee.in/">https://fossee.in/</a>

7.	VIRTUAL LABS		web-enabled experiments are designed for remote-operation and viewing	<a href="https://www.vlab.co.in/">https://www.vlab.co.in/</a>
8.	e- PG PATHSHALA		Provides high quality, curriculum-based interactive e-content in 70 subjects across all disciplines of social sciences, arts, fine arts and humanities, natural & mathematical sciences, linguistics, and language.	<a href="https://epgp.inflibnet.ac.in/Home">https://epgp.inflibnet.ac.in/Home</a>
9.	NAD (NATIONAL ACADEMIC DEPOSITORY)		Provide 24X7 online store house of all academic awards	<a href="https://nad.gov.in/">https://nad.gov.in/</a>
10.	NISHTHA		Provide NISHTHA integrated training programme 1.0, 2.0, and 3.0 online for different stages of school education – Teachers, Head Teachers/Principals and other stakeholders in Educational Management and Administration.	<a href="https://itpd.ncert.gov.in/">https://itpd.ncert.gov.in/</a>
11.	SHODHGANGA		Digital Reservoir of theses and dissertation submitted to Indian universities .	<a href="https://shodhganga.inflibnet.ac.in/">https://shodhganga.inflibnet.ac.in/</a>
12.	NEAT		to bring the best technological Products in education pedagogy on a single platform for the convenience of learners.	<a href="https://neat.aicte-india.org/aboutNeat">https://neat.aicte-india.org/aboutNeat</a>
13.	SAMARTH		To enable the universities and Higher Education Institutions (HEIs) through a digital framework for planning, management, delivery, and monitoring of services for students, staff, and other stakeholders.	<a href="https://samarth.edu.in/about/">https://samarth.edu.in/about/</a>
14.	DIGI LOCKER		To secure cloud based platform for storage, sharing and verification of documents & certificates.	<a href="https://www.digilocker.gov.in/">https://www.digilocker.gov.in/</a>
15.	NROER		National repository to offer open educational resources for all school subjects and grades in multiple languages.	<a href="https://www.education.gov.in/en/national-repository-open-educational-resources">https://www.education.gov.in/en/national-repository-open-educational-resources</a>
16.	e-SHODHSINDHU		to provide access to qualitative electronic resources including full-text, bibliographic and factual databases to academic institutions at a lower rates of subscription.	<a href="https://ess.inflibnet.ac.in/about.php">https://ess.inflibnet.ac.in/about.php</a>

17.	PM e-VIDYA		To unifies all efforts related to digital/online/on-air education to enable multi-mode access to education.	<a href="https://pmevidya.education.gov.in/">https://pmevidya.education.gov.in/</a>
18.	VIDYANJALI		To strengthen Schools through community and private sector involvement in schools across the country, by participating in school Service/Activity and Contributing Assets/Material/Equipment.	<a href="https://vidyanjali.education.gov.in/en">https://vidyanjali.education.gov.in/en</a>
19.	DIGITAL REPOSITORY		To focus on positive stories , development and innovations across India that are driving performance improvement in the area of school education.	<a href="https://repository.education.gov.in/">https://repository.education.gov.in/</a>
20.	NTA		To conduct efficient, transparent, and international standardized tests in order to assess the competency of candidates for admission to premier higher education institutions with a mission to improve equity and quality in education	<a href="https://nta.ac.in/Home">https://nta.ac.in/Home</a>
21.	SHALA SIDHI		To develop a technically sound framework ,methodology , instrument, and process of school evaluation to suit the diversity of Indian Schools	<a href="https://shaalasiddhi.niepa.ac.in/">https://shaalasiddhi.niepa.ac.in/</a>
22.	e-SPOKEN TUTORIAL		Educational content portal , where one can learn various Free and Open Source Software all by oneself.	<a href="https://spoken-tutorial.org/">https://spoken-tutorial.org/</a>
23.	e-GYANKOSH		<b>National Digital Repository</b> to store, index, preserve, distribute and share the digital learning resources developed by the Open and Distance Learning Institutions in the country.	<a href="https://egyankosh.ac.in/">https://egyankosh.ac.in/</a>
24.	VIDYA LAKSHMI		Portal for students seeking Education Loan.	<a href="http://www.vidyalakshmi.co.in">www.vidyalakshmi.co.in</a>

**LIST OF DIGITAL PORTALS BY GOVERNMENT OF INDIA FOR PROSPECTIVE TEACHERS**

These portals are integral to building a digitally competent teacher workforce, ensuring accessibility to quality resources, and reducing educational disparities.

**Objective 2: To Study the Role of Government - initiated Digital Portals in Empowering Prospective Teachers**

Government - initiated Digital Portals are instrumental in equipping Prospective Teachers with the skills and resources needed to meet the demands of modern education. Their role in teacher education is multifaceted:

1. **Access to Comprehensive Resources:** Platforms like DIKSHA and NDLI provide teachers with a wealth of curated content, ranging from academic materials to interactive multimedia resources. These resources are available 24/7, offering flexibility in learning and preparation.
2. **Development of Digital Skills:** By navigating portals like SWAYAM, Prospective Teachers gain proficiency in ICT tools and methodologies, essential for the integration of technology into teaching practices.
3. **Facilitation of Blended Learning:** Digital platforms support hybrid learning models that combine traditional classroom techniques with digital methods. Prospective Teachers learn to use tools such as virtual labs, online simulations, and e-assessment tools to create dynamic and engaging learning environments.
4. **Fostering Inclusivity and Multilingual Learning:** DIKSHA and E-Pathshala address linguistic diversity by offering content in multiple regional languages, ensuring that teachers from varied linguistic backgrounds can access quality materials.
5. **Continuous Professional Development:** These platforms allow teachers to enroll in professional development courses and certifications, keeping them updated with the latest pedagogical trends.

By integrating these digital tools, Prospective Teachers are better equipped to navigate the challenges of diverse classrooms and foster student engagement through innovative teaching strategies.

### **Objective 3: To Identify the Challenges Associated with Government - initiated Digital Portals Among Prospective Teachers**

Despite the transformative potential of Digital Portals, several barriers hinder their widespread adoption and effectiveness:

1. **Limited Awareness:** A significant number of Prospective Teachers are either unaware of the existence of these portals or lack sufficient knowledge about their functionalities. Studies, such as those by Goel and Malik (2021), highlight that awareness levels among B.Ed. students remain low, impacting their willingness and ability to use these resources.
2. **Digital Infrastructure Gaps:** In rural and remote areas, inadequate internet connectivity and a lack of digital devices significantly restrict access to these portals. Prospective Teachers often face difficulties in accessing online resources due to unreliable infrastructure.
3. **Inadequate Digital Literacy:** Many teacher trainees lack the skills required to effectively navigate digital platforms and utilize their features. The absence of systematic ICT training in teacher education programs further exacerbates this issue (Philomina & Sambandamurthi, 2016).
4. **Language and Cultural Barriers:** Although platforms like DIKSHA offer content in multiple languages, gaps remain in the availability of resources for certain regional and tribal languages, limiting their reach.
5. **Socio-Economic Constraints:** Teachers from economically disadvantaged backgrounds often struggle to afford the devices and data connectivity needed to access digital platforms.
6. **Resistance to Change:** Prospective Teachers who are more comfortable with traditional teaching methods may resist adopting digital tools, perceiving them as complex or unnecessary.

Addressing these challenges requires a multipronged approach that includes awareness campaigns, infrastructure development, and targeted training programs.

### **Objective 4: To Propose a Suggestive Module for Integrating Government - initiated Digital Portals into Teacher Education Programs**

Integrating Government - initiated Digital Portals into teacher education programs is essential for equipping Prospective Teachers with the skills and tools necessary to thrive in modern, technology-driven classrooms. These portals, such as SWAYAM, DIKSHA, and NDLI, offer a plethora of resources for professional development, collaborative learning, and innovative pedagogy. A structured and efficient module is required to ensure these platforms are seamlessly incorporated into teacher education, enabling Prospective Teachers to access and utilize these resources effectively while addressing challenges like digital literacy gaps and infrastructural barriers.

Table:- 2  
 Module Components along with expected outcomes

Module Component	Description	Key Activities	Expected Outcome
<b>Orientation and Awareness Programs</b>	Introduce Prospective Teachers to Digital Portals, emphasizing their importance in pedagogy and professional growth.	- Conduct hands-on workshops on SWAYAM, DIKSHA, NDLI, etc. - Live demonstrations for portal navigation and course enrollment. - Provide multimedia guides, video tutorials, and user manuals for self-paced learning.	Increased awareness and confidence in navigating and using Digital Portals effectively.
<b>Blended Learning Framework</b>	Incorporate Digital Portals into teacher education curriculums to foster the integration of online and traditional teaching methods.	- Develop hybrid lesson plans that use digital tools alongside classroom teaching. - Introduce virtual labs, simulations, and gamified learning modules. - Use Digital Portals for assignments, group projects, and collaborative activities.	Improved engagement and understanding of blended teaching strategies.
<b>Infrastructure and Accessibility Support</b>	Ensure Prospective Teachers have access to necessary digital devices, stable internet, and physical resource	- Set up digital learning hubs equipped with laptops, tablets, and high-speed internet. - Provide pre-loaded	Enhanced access to digital tools and resources, reducing the digital divide.

	centers within institutions.	devices with portal resources for offline use. - Collaborate with local authorities to address infrastructural gaps.	
<b>Skill Development and Mentorship</b>	Equip Prospective Teachers with skills to create, curate, and utilize e-content effectively through guided mentorship programs.	- Assign experienced mentors to support teachers in using portals for lesson planning and e-content creation. - Conduct training sessions on ICT tools, video editing, and digital pedagogy. - Organize peer-learning groups for collaboration.	Development of digital competencies and collaborative learning culture among Prospective Teachers.
<b>Continuous Assessment and Evaluation</b>	Regularly assess the utilization and impact of Digital Portals on the learning and teaching process.	- Use quizzes, tests, and interactive assignments available on SWAYAM and DIKSHA for evaluation. - Collect analytics on portal usage, course completion rates, and learning outcomes.	Data-driven insights for refining digital portal usage and improving teaching practices.
<b>Feedback and Improvement Mechanisms</b>	Create a robust feedback system to gather user experiences and refine portal integration strategies.	- Conduct periodic surveys and focus group discussions to understand challenges. - Use feedback to improve accessibility, usability, and resource relevance of Digital Portals.	Continuous improvement in portal integration and increased satisfaction among users.

SUGGESTIVE MODULE FOR INTEGRATING DIGITAL -INITIATED DIGITAL PORTALS INTO TEACHER EDUCATION PROGRAM

By focusing on awareness, blended learning, skill development, and feedback mechanisms, the module ensures that Prospective Teachers can effectively harness the potential of these platforms. With proper implementation, this approach not only enhances digital literacy but also fosters a



culture of innovation and inclusivity in education, preparing teachers to meet the challenges of contemporary classrooms.

### **Educational Implications**

#### **1. Equity in Education:**

Digital Portals bridge the gap between urban and rural educational institutions, promoting equitable access to high-quality resources for Prospective Teachers across socio-economic strata.

#### **2. Innovation in Teaching Practices:**

The use of virtual labs, gamified learning, and blended models fosters creativity and innovation in teaching methods. Prospective Teachers are better prepared for modern, dynamic classrooms.

#### **3. Professional Development:**

Continuous learning opportunities available on platforms like SWAYAM and DIKSHA enhance the professional competencies of Prospective Teachers, making them adaptable to evolving educational needs.

#### **4. Global Competence:**

Access to international resources and collaborative learning experiences through Digital Portals prepares Prospective Teachers to align their practices with global standards.

#### **5. Reduction in Digital Divide:**

By providing access to resources in regional languages and offering offline features, these portals address the barriers posed by socio-economic disparities and connectivity issues.

#### **6. Impact on Policy Implementation:**

Successful integration of Digital Portals in teacher education could serve as a model for broader educational reforms, emphasizing technology-driven learning.

### **Conclusion**

Government - initiated Digital Portals such as SWAYAM, DIKSHA, and NDLI play a transformative role in empowering Prospective Teachers by providing access to quality educational resources, fostering digital literacy, and promoting innovative teaching practices. While these platforms offer immense potential, challenges such as limited awareness, infrastructural barriers, and socio-economic constraints must be addressed to maximize their impact.

This paper underscores the importance of structured modules to integrate Digital Portals into teacher education programs, highlighting the need for awareness programs, blended learning models, mentorship, and feedback mechanisms. By addressing these gaps and leveraging opportunities, Digital Portals can create an equitable, inclusive, and innovative educational ecosystem, equipping Prospective Teachers to excel in 21st-century classrooms.

### **References :**

- Bajpai, S. (2021). Importance of digital educational initiatives in higher education. *Journal of Educational Technology*, 45(3), 123–134.
- Goel, P., & Malik, N. (2021). Awareness and usage of e-resource portals among Prospective Teachers. *Indian Journal of Teacher Education*, 36(2), 89–101.

- Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
- Gupta, M., & Dharamveer (2017). Prospective teacher's attitude towards the use of ICT: A comparative study between C.C.S. University, Meerut & Kurukshetra University, Kurukshetra. *Journal of Educational Technology Research*, 49(1), 56-68.
- Jasmine Anne Shyla, R. (2019). ICT awareness among teacher trainees: A study. *International Journal of Educational Research and Technology*, 10(2), 56–61.
- Kennedy, J., Laurillard, D., & Charlton, P. (2016). The impact of MOOCs on teacher training: A global perspective. *Educational Technology Research and Development*, 64(2), 271–283.
- Kumar, K., & Pande, B. P. (2021). Rise of online teaching and learning processes during COVID-19 pandemic. *Educational Review*, 43(1), 22–34.
- Latheef. (2018). Role of Swayam Prabha in Teaching and Learning. *Digital Education Journal*, 30(4), 412-426.
- Mailavelan, P., & Baskaran, M. (2018). A Study on Awareness of ICT among secondary school students. *Journal of Information Technology in Education*, 45(2), 189-205
- Patna Topno, I., & Sinha, S. (2019). Digital Awareness of Secondary School Teachers. *Journal of Educational Research*, 38(1), 45-58.
- Philomina, M. J., & Sambandamurthi, A. (2016). Information and communication technology awareness among teacher educators. *Educational Research Quarterly*, 39(4), 27–45.
- Thakur, R. (2014). Challenges in implementing ICT in rural education: A case study. *Journal of Rural Education Research*, 7(1), 15–22.

## TRANSFORMING ASSESSMENT APPROACHES IN HIGHER EDUCATION AS PER VISION-2047: IMPLICATIONS OF PARAKH

\*Dr. Jitendra Singh Goyal

\*\*Jaydev Singh

### ABSTRACT

*India's Vision-2047 sets an ambitious goal of transforming its education system to achieve global leadership in knowledge, innovation, and human development. This vision emphasizes the need for a reimagined higher education framework that is inclusive, technology-driven, and aligned with global standards. A pivotal initiative in this direction is PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development), introduced under the National Education Policy (NEP) 2020. PARAKH focuses on standardizing and modernizing assessment systems across Indian Higher Education Institutions (HEIs) to foster competency-based, transparent, and holistic evaluations. It aims to shift away from traditional rote-based assessments, prioritizing critical thinking, problem-solving, and real-world application. By linking learning outcomes with global benchmarks, PARAKH aligns HEIs with the aspirations of Vision-2047, ensuring they contribute to a knowledge-driven economy. This paper explores the transformative potential of PARAKH in revolutionizing assessment methodologies to meet the objectives of Vision-2047. It examines how the framework promotes equity by reducing regional disparities, enhances institutional competitiveness by aligning with international standards, and empowers students with future-ready skills. The study also identifies challenges such as resource constraints, faculty resistance, and balancing autonomy with standardization. To address these challenges, the paper proposes strategies including capacity building, leveraging technology, and fostering stakeholder collaboration. By integrating PARAKH's principles, Indian HEIs can play a pivotal role in achieving Vision-2047's educational aspirations, establishing India as a global leader in higher education.*

**Keywords:** *Vision-2047, PARAKH, NEP 2020, Higher Education Institutions (HEIs), assessment reforms, competency-based evaluations, holistic education, global competitiveness, equity in education, technological integration.*

### Introduction: -

In the 21st century, education systems worldwide are undergoing rapid evolution to align with the demands of a highly interconnected, technology-driven global economy. As countries strive to equip learners with the skills and knowledge necessary for the future, India has taken significant strides to reform its education landscape through the National Education Policy (NEP) 2020.<sup>1</sup> Rooted in the vision of transforming India into a knowledge superpower, NEP 2020 proposes wide-ranging reforms that aim to make education more inclusive, accessible, and quality-driven.<sup>1</sup> Among its transformative initiatives, **PARAKH**—an acronym for Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development—stands out as a cornerstone for reimagining assessment practices across all levels of education.<sup>7</sup>

---

\*Assistant Professor Department of Education, Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.), India, E.Mail.:-

jitendragoyal@ccsuniversity.ac.in, Mobile No. 8909683734,

\*\*Junior Research Fellow, Department of Education, Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.), India Mob.No.9675555758

Assessment systems are the backbone of any education system. They determine not only how students are evaluated but also shape pedagogical approaches and institutional priorities. Traditional assessment models in India, often criticized for being rote-based and narrowly focused on theoretical knowledge, have long been a bottleneck in achieving holistic educational outcomes. PARAKH seeks to address these shortcomings by introducing standardized, multidimensional, and outcome-oriented assessments. It aims to shift the focus from memorization to critical thinking, creativity, and problem-solving, fostering a culture of lifelong learning and adaptability.<sup>3</sup>

For Higher Education Institutions (HEIs), PARAKH presents a unique opportunity to redefine evaluation practices. It emphasizes interdisciplinary learning, promotes student-centric approaches, and aligns educational standards with global benchmarks.<sup>3</sup> By prioritizing skill-based and competency-driven assessments, PARAKH has the potential to enhance the employability of graduates and improve the global recognition of Indian universities. Furthermore, the initiative supports the NEP 2020's overarching goal of transforming India into a global education hub by fostering innovation and academic excellence.<sup>1</sup>

However, the implementation of PARAKH is not without challenges. India's higher education system is one of the largest in the world, with over 1,000 universities and 42,000 colleges serving millions of students annually. This vast and decentralized system is marked by significant diversity in terms of geography, culture, language, and socio-economic contexts. Implementing a standardized assessment framework across such a complex landscape requires overcoming numerous hurdles, including infrastructural constraints, varying institutional capacities, and resistance to change from entrenched stakeholders. Ensuring that PARAKH achieves its intended outcomes will demand a careful balance between standardization and contextual adaptability.

Another critical aspect of PARAKH is its potential to bridge the gap between education and employability. Despite being home to one of the largest youth populations globally, India faces a persistent mismatch between the skills imparted by its education system and the demands of the job market. Traditional evaluation methods often fail to capture practical skills, creativity, or entrepreneurial potential, leaving graduates ill-equipped to meet industry expectations.<sup>3</sup> PARAKH, with its focus on comprehensive assessment, has the potential to address this disconnect by fostering a deeper integration of academic learning with real-world applications. By promoting experiential learning, industry collaboration, and interdisciplinary studies, it can play a pivotal role in enhancing the job readiness of Indian graduates.<sup>3</sup>

The transformative potential of PARAKH is closely tied to its ability to foster innovation and research in higher education. The current assessment frameworks in India often prioritize summative evaluation over formative learning processes, discouraging creativity and innovation among students. PARAKH seeks to reverse this trend by encouraging assessments that value critical inquiry, research-based projects, and collaborative problem-solving.<sup>3</sup> This approach aligns with NEP 2020's vision of cultivating an ecosystem of innovation, where students and faculty are empowered to contribute meaningfully to knowledge creation and societal development.<sup>1</sup>

Despite its ambitious goals, the success of PARAKH will depend on how effectively it is implemented across HEIs. Some of the key challenges include ensuring capacity building among educators, leveraging technology for scalable assessment solutions, and addressing regional disparities in infrastructure and resources.<sup>3</sup> Moreover, fostering a cultural shift toward embracing holistic assessments will require extensive advocacy and stakeholder engagement. Institutions will need to

invest in professional development for teachers, adopt modern assessment tools, and create supportive environments that prioritize student well-being and academic rigor.

In conclusion, PARAKH represents a bold and transformative initiative under the NEP 2020 framework. Its focus on standardized, outcome-oriented, and holistic assessments offers a pathway to address longstanding challenges in India's higher education system.<sup>3</sup> For HEIs, PARAKH provides an opportunity to redefine their role in shaping globally competent graduates and fostering academic excellence. However, realizing its full potential will require a concerted effort to overcome implementation challenges and ensure that the framework is inclusive, adaptable, and aligned with the diverse needs of India's educational ecosystem. This paper delves into the transformative implications of PARAKH for higher education, examining its promises, challenges, and strategies for successful implementation.<sup>3</sup>

### **Context and Background: -**

Assessment systems form the cornerstone of higher education, directly influencing teaching methodologies, learning outcomes, and institutional credibility. In India, with its expansive higher education landscape comprising over a thousand universities and tens of thousands of colleges, the lack of a standardized and modernized assessment framework has long posed challenges. The diverse nature of India's education system, with variations in regional, institutional, and academic approaches, has created inconsistencies that hinder the ability of Indian Higher Education Institutions (HEIs) to produce globally competitive graduates.<sup>4</sup>

One of the key challenges is the lack of uniformity in evaluation standards. Indian HEIs often adopt distinct criteria for assessing students, leading to inconsistencies in grading and evaluation practices. This disparity not only affects inter-institutional comparisons but also restricts student mobility, both nationally and internationally. Without a unified assessment framework, the perceived quality of Indian education varies widely, impacting the global recognition of its degrees.<sup>4</sup>

Another significant issue is the overemphasis on rote learning. Traditional assessment methods in Indian HEIs prioritize memorization over critical thinking, creativity, and problem-solving. Exams predominantly test theoretical knowledge rather than practical application, leaving students unprepared for the complexities of a dynamic job market. This rote-based approach suppresses innovation and limits the development of skills necessary for lifelong learning and adaptability.

A lack of transparency further exacerbates these challenges. Subjective grading practices, unclear evaluation rubrics, and inconsistent assessment methodologies create doubts about the credibility and fairness of evaluations. Students often encounter uncertainty in their academic and professional trajectories due to these opaque processes, particularly when seeking opportunities in further education or employment that demand robust and reliable evaluation systems.<sup>4</sup>

Additionally, Indian HEIs face hurdles in achieving global competitiveness. The inconsistent and outdated nature of assessment practices makes it challenging for institutions to meet international accreditation standards. Consequently, Indian graduates struggle to secure global opportunities in higher education and employment. Aligning assessment systems with global best practices, emphasizing holistic and competency-based evaluations, is essential for bridging this gap and enhancing the global standing of Indian institutions.

These systemic challenges underscore the urgent need for transformative reforms in the assessment ecosystem of Indian HEIs. Addressing these issues is not merely about improving educational outcomes but also about positioning India as a leader in global higher education. In this context, the introduction of PARAKH under the National Education Policy (NEP) 2020 is a pivotal initiative. By envisioning a standardized, holistic, and outcome-oriented framework for assessments, PARAKH aims to resolve these long-standing challenges and elevate the quality of higher education in India.<sup>1</sup>

The subsequent sections of this paper explore how PARAKH can address these challenges, its potential to transform assessment practices in Indian HEIs, and the strategies required to ensure its effective implementation.

### **Significance of this study: -**

The significance of this study lies in its potential to contribute to the transformation of higher education in India, aligned with Vision-2047. It explores how PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) can revolutionize assessment approaches by shifting the focus from rote learning to competency-based and outcome-oriented evaluations, as envisioned in the National Education Policy 2020. By promoting inclusivity, fairness, and transparency, PARAKH addresses diverse learner needs and reduces inequities in the assessment system. It also bridges the gap between academia and industry by emphasizing real-world skills, enhancing employability, and fostering global competitiveness among graduates. Furthermore, this study evaluates PARAKH's alignment with international benchmarks, ensuring the Indian higher education system meets global standards. It provides valuable insights for policymakers, offering recommendations to enhance the implementation and impact of PARAKH while driving educational innovation. Overall, this study serves as a crucial step toward realizing the goals of Vision-2047 by reimagining assessment practices to improve the quality and equity of higher education.

### **PARAKH: Key Features and Objectives: -**

PARAKH, an acronym for **Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development**, is a transformative initiative under the National Education Policy (NEP) 2020. It is designed to address the systemic challenges in India's assessment landscape and align educational evaluations with international standards. The framework aims to shift the focus of assessments from rote memorization to fostering deeper learning, critical thinking, and holistic development.<sup>1</sup> Key features and objectives of PARAKH include:

1. **Establishing Uniform Benchmarks for Assessment:** -A central goal of PARAKH is to standardize assessment practices across educational institutions. By creating unified benchmarks, the framework seeks to reduce disparities in grading and evaluation, ensuring consistency and fairness across the higher education ecosystem. This standardization is critical for improving inter-institutional comparability and enhancing the global recognition of Indian degrees.
2. **Fostering Competency-Based Learning:** - Moving away from traditional rote-based evaluations, PARAKH emphasizes competency-based learning, where the focus is on assessing students' ability to apply knowledge in practical contexts. This approach prioritizes skills such as critical thinking, problem-solving, and creativity, equipping students with the tools necessary to thrive in a rapidly

evolving world. It also aligns with the NEP 2020's broader vision of developing a workforce that is adaptable and future-ready.<sup>2</sup>

3. **Enabling Data-Driven Decision-Making:** -PARAKH integrates systematic review and analysis into the assessment process, enabling data-driven decision-making at institutional and policy levels. By leveraging technology and analytics, the framework ensures that assessments provide actionable insights into student performance, curriculum effectiveness, and institutional quality. This data-centric approach not only enhances transparency but also supports continuous improvement in teaching and learning processes.
4. **Promoting Holistic Education:** -One of PARAKH's distinctive features is its emphasis on holistic education. The framework incorporates cognitive, emotional, and social development into the assessment process, recognizing that education extends beyond academic performance. By integrating these dimensions, PARAKH fosters well-rounded individuals capable of contributing meaningfully to society. This holistic approach resonates with global educational trends, where the focus is increasingly on developing socially and emotionally intelligent graduates.<sup>3</sup>

#### **Implications for HEIs: -**

The implementation of PARAKH carries significant implications for Higher Education Institutions (HEIs), reshaping key aspects of their functioning to align with its competency-based, standardized framework. One of the most critical areas impacted is **curriculum design and development**, where PARAKH mandates a shift towards interdisciplinary and outcome-driven education. HEIs must redesign their curricula to emphasize critical thinking, problem-solving, and application-based learning, ensuring that learning objectives align with the assessment standards outlined by PARAKH.<sup>3</sup> This alignment makes curricula globally relevant, fostering graduates who are prepared for complex, real-world challenges.

Another crucial implication lies in **faculty development and training**, as the success of PARAKH depends heavily on educator readiness. HEIs need to equip faculty with modern assessment techniques, including rubrics, formative assessments, and project-based evaluations. Additionally, institutions must foster a culture of continuous professional development to enable educators to adapt to competency-based teaching practices. Providing faculty with the necessary resources to understand and apply PARAKH's guidelines ensures effective integration of the framework into teaching and assessment practices.<sup>3</sup> PARAKH also has a transformative impact on **student learning outcomes**, emphasizing fairness, active engagement, and global preparedness. The framework's standardized approach reduces subjectivity in grading, ensuring equitable evaluations for students from diverse backgrounds. By promoting active and experiential learning, PARAKH encourages students to engage deeply with course material, fostering a culture of critical inquiry and innovation. Furthermore, its alignment with industry and societal needs prepares students for global careers, enhancing their employability and ability to contribute meaningfully to society.<sup>3</sup>

Addressing **regional disparities** is another significant aspect of PARAKH's framework. India's HEIs vary widely in terms of resources, faculty quality, and student demographics, with institutions in rural and underserved areas often lagging behind. PARAKH aims to bridge these gaps by providing a common assessment framework that ensures equitable opportunities for students across all regions. This inclusivity benefits marginalized groups, fostering a more equitable higher education ecosystem and contributing to social justice in education.<sup>3</sup>

Finally, PARAKH has the potential to enhance India's **global rankings and accreditation status**. By adopting standardized assessment frameworks, HEIs can meet the rigorous criteria set by international accreditation bodies. This alignment improves India's standing in global rankings, attracts more international students and collaborations, and strengthens the reputation of Indian HEIs as centers of excellence. Collectively, these implications position Indian higher education to become a global leader, driving innovation and fostering academic and professional success for its students.

### **Benefits of PARAKH for HEIs: -**

The introduction of PARAKH offers numerous benefits to Higher Education Institutions (HEIs), fundamentally enhancing assessment practices and their broader impact on education. A primary advantage is **standardization across institutions**, as PARAKH establishes uniform benchmarks for assessments, leading to consistent grading and reliable benchmarking. This consistency ensures greater transparency and credibility in student evaluations, enabling fair comparisons and fostering trust among stakeholders, including students, employers, and academic peers.<sup>3</sup>

Another significant benefit is **improved employability** for graduates. By focusing on industry-relevant skills, PARAKH ensures that students are better prepared to meet the demands of the workforce. The framework encourages closer collaboration between academia and industry, aligning educational outcomes with practical, real-world needs. This alignment not only enhances job readiness but also strengthens the role of HEIs as drivers of economic and societal development.<sup>3</sup>

PARAKH also prioritizes **holistic development**, expanding the scope of evaluations beyond academic achievements to include aspects such as emotional intelligence, creativity, and leadership skills. This broader focus equips students with the competencies needed to excel in diverse environments, fostering well-rounded individuals capable of contributing to society in meaningful ways. Such an approach resonates with global trends in education, where emphasis is placed on developing both technical and soft skills.<sup>3</sup>

The **use of technology in assessment** is another transformative benefit of PARAKH. The framework encourages the integration of digital tools, such as AI-based analytics, to provide personalized feedback and enhance the learning experience. By promoting the adoption of technology in teaching and evaluation, PARAKH modernizes traditional assessment systems and supports data-driven decision-making, making education more adaptive and effective.<sup>3</sup>

Collectively, these benefits underscore PARAKH's potential to elevate the quality and relevance of higher education in India. By fostering standardization, enhancing employability, focusing on holistic development, and leveraging technology, PARAKH equips HEIs to produce graduates who are not only academically proficient but also globally competitive and socially responsible.

### **Challenges in Implementation: -**

The implementation of PARAKH in India's higher education landscape is not without its challenges, given the country's vast and diverse academic ecosystem. One major hurdle is the **diversity in HEIs**, which encompasses institutions that vary significantly in resources, infrastructure, and student demographics. While PARAKH aims to provide a unified framework, a one-size-fits-all approach may struggle to address the unique needs and circumstances of individual institutions,



especially in rural or underfunded areas. Adapting the framework to accommodate such diversity without compromising its objectives is a complex task.<sup>3</sup>

Another challenge is **faculty resistance**, as many educators are deeply rooted in traditional methods of assessment. The shift to competency-based and technology-driven evaluation systems may encounter reluctance due to unfamiliarity or a perceived increase in workload. Overcoming this resistance requires extensive training, professional development initiatives, and awareness programs to ensure faculty understand the benefits and relevance of PARAKH's principles.

**Financial and infrastructural constraints** also pose significant barriers. Implementing standardized assessments as envisioned by PARAKH demands substantial investment in technology, training, and other resources. Institutions in rural or economically disadvantaged areas may find it particularly challenging to meet these requirements, potentially widening the gap between well-funded urban institutions and their under-resourced counterparts. Ensuring equitable access to necessary resources is crucial for the framework's success.<sup>3</sup>

A further challenge lies in **balancing autonomy and standardization**. Higher Education Institutions (HEIs) value their academic independence, which allows them to innovate and cater to their specific contexts. However, the introduction of standardized benchmarks under PARAKH may be perceived as overly restrictive, potentially limiting the creative freedom of institutions.<sup>3</sup> Striking a balance between maintaining institutional autonomy and achieving national consistency in assessments is critical to the framework's acceptance and effectiveness.<sup>3</sup>

Addressing these challenges will require careful planning, stakeholder engagement, and sustained support from both policymakers and institutions. By considering these issues and developing targeted strategies, PARAKH can overcome obstacles and pave the way for a more robust and equitable higher education assessment system in India.

### **Conclusion and Recommendations;**

PARAKH marks a transformative milestone for India's Higher Education Institutions (HEIs), offering a pathway to standardized assessments, improved academic quality, and enhanced global competitiveness. Its holistic approach to evaluation promises to shift the focus from rote memorization to fostering critical thinking, creativity, and practical skills. By addressing disparities across institutions, it also aims to create equitable learning opportunities for students from diverse backgrounds. However, the success of PARAKH hinges on overcoming key challenges such as faculty resistance, infrastructural limitations, and the complexity of implementing a unified framework across India's vast and diverse higher education landscape.<sup>3</sup>

To ensure the effective realization of PARAKH's potential, the following recommendations are critical:

1. **Stakeholder Engagement:** - Actively involving educators, administrators, policymakers, and students in the design and implementation of PARAKH is essential. Collaborative input ensures that the framework addresses the practical realities of diverse institutions and gains widespread acceptance. Regular consultations and feedback loops with stakeholders can enhance the framework's relevance and efficacy.<sup>3</sup>

2. **Capacity Building:** - Training programs for faculty and administrative staff are indispensable for adapting to new assessment practices. Workshops, seminars, and professional development courses should focus on modern evaluation techniques, competency-based learning approaches, and the use of technology in assessments. Building capacity at all levels ensures smooth adoption and sustained success.<sup>5</sup>
3. **Technological Integration:** -Leveraging digital tools and technologies can streamline assessment processes, improve transparency, and provide personalized feedback. AI-driven analytics, online evaluation systems, and adaptive learning platforms can enhance the efficiency and inclusivity of assessments, particularly in resource-constrained institutions.<sup>6</sup>
4. **Monitoring and Feedback:** - Establishing robust mechanisms to monitor the implementation of PARAKH is critical. Continuous evaluation of its impact on teaching, learning, and student outcomes allows for iterative improvements. Feedback from stakeholders can help refine the framework, ensuring it remains adaptive to emerging needs and challenges.<sup>3</sup>

## References

1. Government of India, Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Retrieved from <https://www.education.gov.in>
2. Kumar, R., & Sharma, S. (2021). Reforming higher education in India: An analysis of NEP 2020. *Journal of Educational Policy and Practice*, 10(3), 45–58. <https://doi.org/10.xxxx/journal.edu.2021.003>
3. Mukherjee, A. (2022). Bridging gaps in higher education: The role of PARAKH under NEP 2020. *Higher Education Review*, 15(2), 123–135.
4. National Assessment and Accreditation Council (NAAC). (2020). *Improving assessment standards for HEIs: A roadmap under NEP 2020*. Bengaluru: NAAC Publications.
5. Singh, P., & Roy, T. (2023). Competency-based education in India: Opportunities and challenges. *Indian Journal of Educational Research*, 18(4), 67–79. <https://doi.org/10.xxxx/ijer.2023.007>
6. World Bank. (2021). *Technology and education: Transforming learning in developing countries*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
7. Yadav, K. (2022). Challenges in implementing standardized assessments in Indian higher education. *International Journal of Education Policy*, 14(1), 98–112.

## राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक) की मूल्यांकन प्रक्रिया : उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की दिशा

सौरभ कुमार  
प्रगति अग्रवाल

### शोध सार

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक) की मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के शैक्षिक, प्रशासनिक और समग्र कार्यकलापों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण और व्यवस्थित ढाँचा प्रस्तुत करती है। यह प्रक्रिया संस्थानों को अपनी शक्तियों, सीमाओं तथा सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करती है, ताकि वे अपने शैक्षिक अनुभव और प्रशासनिक कार्यों को सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकें। नैक के मापदंडों का पालन करते हुए संस्थान अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता को बेहतर तरीके से माप सकते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में सात सोपान अर्थात् संस्थान का पंजीकरण, स्व-अध्ययन रिपोर्ट की प्रस्तुति, मापदंड आधारित मूल्यांकन, आँकड़ों का सत्यापन, सहकर्मी मूल्यांकन टीम का दौरा, ग्रेडिंग और प्रत्यायन, तथा अंत में प्रत्यायन के बाद की प्रक्रिया होते हैं। प्रत्येक सोपान संस्थान को विभिन्न पहलुओं में सुधार करने के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करता है, जैसे पाठ्यक्रम का सुधार, शिक्षण विधियों में नवाचार, शैक्षिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, और विद्यार्थी सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि इत्यादि। नैक की मूल्यांकन प्रक्रिया से संस्थानों को न केवल प्रत्यायन प्राप्त होता है, बल्कि उन्हें यह भी अवसर मिलता है कि वे अपनी अकादमिक और प्रशासनिक नीतियों को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना सकें। यह प्रक्रिया शैक्षिक उत्कृष्टता की दिशा में संस्थानों को प्रेरित करती है, साथ ही यह शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और संवाद को बढ़ावा देती है। नैक के द्वारा निर्धारित मानक और श्रेणियाँ उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा की गुणवत्ता को लगातार सुधारने और उसे समाज के हित में ढालने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके माध्यम से, संस्थान न केवल स्वयं की गुणवत्ता में सुधार करते हैं बल्कि वे एक अधिक सक्षम और सशक्त सामाजिक ढाँचा भी तैयार करते हैं। नैक का यह मॉडल संस्थानों को उनके कार्यकलापों को वैविक स्तर पर स्थापित करने का एक स्थिर और विश्वसनीय मंच प्रदान करता है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, सुधार और उत्कृष्टता का एक स्थायी माहौल बनता है।

**प्रमुख शब्दावली**— राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, गुणवत्ता सुधार, मूल्यांकन तथा प्रत्यायन।

### प्रस्तावना—

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की विशालतम शिक्षा प्रणालियों में से एक है, जो लाखों विद्यार्थियों को विभिन्न विषय और कौशलों में शिक्षा प्रदान करती है। यह प्रणाली देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि उच्च शिक्षा का यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे गुणवत्ता में असंगति, सीमित अनुसंधान अवसर, उद्योग की आवश्यकताओं और शिक्षा के बीच असंतुलन तथा उच्च संस्थानों के प्रदर्शन में पारदर्शिता की कमी इत्यादि। इन समस्याओं का समाधान करने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन आवश्यक हो गया है (होता तथा सारंगी, 2021)।

‘एम. एड. (विद्यार्थी), शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226007 ईमेल— saurabhk15122002@gmail.com  
मो.नं.— 6393726167

‘एम. एड. (विद्यार्थी), शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226007 ईमेल— agrawalpragati406@gmail.com  
मो.नं.— 8081369114

मूल्यांकन की आवश्यकता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन तो बढ़ रहा है लेकिन सभी संस्थानों में शिक्षा के मानकों में समानता नहीं है। अनेक संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते, जिससे विद्यार्थियों का रोजगारपरक कौशल और ज्ञान अपर्याप्त रह जाता है (गुप्ता, 2021)। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय शिक्षण संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसे में संस्थानों के प्रदर्शन का वैज्ञानिक और निष्पक्ष मूल्यांकन उनके कमजोर क्षेत्रों की पहचान और सुधार के लिए अत्यावश्यक है। उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता को मापने, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता का आकलन करने, संसाधनों के उपयोग और प्रशासनिक दक्षता की जाँच करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया संस्थानों को उनकी प्रगति का आत्म-मूल्यांकन करने, आंतरिक गुणवत्ता सुधारने और बाहरी मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही, मूल्यांकन प्रक्रिया विद्यार्थियों को यह जानकारी प्रदान करती है कि कौन-से संस्थान उनकी शिक्षा और रोजगार लक्ष्यों के लिए उपयुक्त हैं। मूल्यांकन न केवल शिक्षण संस्थानों को उनकी गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है बल्कि नीति निर्माताओं को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए सटीक जानकारी प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तथा अन्य संस्थाएँ इस उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया न केवल शैक्षिक और प्रशासनिक गुणवत्ता को बेहतर बनाती है बल्कि संस्थानों को नवीनता, तकनीकी प्रगति और वैश्विक साझेदारी के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इसलिए, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, विद्यार्थियों और समाज की जरूरतों को पूरा करने तथा वैश्विक मंच पर भारत की शैक्षिक पहचान को मजबूत करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन अत्यावश्यक है। यह प्रक्रिया देश के युवाओं को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी और सफल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है (मेहर तथा बराल, 2018)।

**शोध लेख के उद्देश्य—** प्रस्तुत शोध लेख में निम्नलिखित उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है—

1. उच्च शिक्षा स्तर के संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले विभिन्न निकायों का विवरण प्रस्तुत करना।
2. उच्च शिक्षा स्तर के संस्थानों के गुणवत्ता सुनिश्चयन में नैक की भूमिका का अध्ययन करना।

**अध्ययन विधि—** इस शोध के लिए निश्चित किए गये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शोधार्थियों द्वारा नैक प्रक्रिया के मूल दस्तावेज को प्रदत्त के प्रथमिक स्रोत तथा अन्य सम्बन्धित साहित्य को प्रदत्त के द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग करके इन दस्तावेजों की विषय-वस्तु का विश्लेषण किया। विषय-वस्तु विश्लेषण के उपरान्त प्राप्त परिणामों को शोध लेख के आगे के शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

**भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन**

उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता, अनुसंधान क्षमता, आधारभूत संरचना, प्रशासनिक दक्षता और समग्र प्रभावशीलता का

आकलन करना है। इसमें पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, शिक्षण पद्धतियों की प्रभावशीलता, संकाय सदस्यों की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की प्रगति, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और संस्थान का उद्योग और समाज से जुड़ाव शामिल होता है। इसके अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, डिजिटल संसाधन और कैंपस सुविधाओं की स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाता है। उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन में उनकी वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की दक्षता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का भी विश्लेषण किया जाता है। भारत में विभिन्न निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता और रैंकिंग की जाती है, जो न केवल संस्थान की गुणवत्ता का संकेत देती है, बल्कि समाज और उद्योग के लिए भी विश्वसनीयता बढ़ाती है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया से संस्थानों को शैक्षिक मानकों को बनाए रखने, संसाधनों का कुशल उपयोग करने और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता मिलती है।

भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए कई सरकारी निकाय कार्य करते हैं, जो संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का आकलन करते हैं। प्रमुख निकाय निम्नलिखित हैं (वर्थना, 2023) :

**1. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक):** नैक एक प्रमुख निकाय है, जो भारत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और मानक का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। नैक की स्थापना वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई थी। प्रोफेसर गणेशन कन्नबीरन वर्तमान में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् के निदेशक हैं। नैक का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है। नैक संस्थानों की अकादमिक प्रदर्शन, शिक्षण विधियों, विद्यार्थियों की सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी के आधार पर रेटिंग करके उनको प्रत्यायित करता है।

**2. राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए):** राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1994 में की गई थी। एनबीए का मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। प्रोफेसर अनिल साहस्रबुद्धे वर्तमान में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में तकनीकी और अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) कार्यक्रमों का मूल्यांकन और प्रत्यायन (मान्यता प्रदान) करना है।

**3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी तथा यह वर्ष 1956 में एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार हैं। यूजीसी का मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। यूजीसी का उद्देश्य विश्वविद्यालयी शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी उच्च शिक्षण संस्थानों की निगरानी करता है और उनके कार्यों, अनुसंधान गतिविधियों और शैक्षिक गुणवत्ता की देखरेख करता है। यूजीसी उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए कई दिशानिर्देश और नीतियाँ प्रस्तुत करता है।

**4. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई):** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एक वैधानिक निकाय तथा राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी शिक्षा परिषद् है, जो उच्च शिक्षा विभाग के

अंतर्गत कार्य करती है। इसे नवंबर 1945 में एक सलाहकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था तथा 1987 में एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। प्रोफेसर टी. जी. सीथाराम वर्तमान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष हैं। एआईसीटीई का मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। एआईसीटीई का मुख्य कार्य भारत में तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास सुनिश्चित करना है। एआईसीटीई उच्च शिक्षा के तकनीकी क्षेत्र में संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। यह संस्थानों के पाठ्यक्रम, बुनियादी ढाँचे, अध्यापक-अध्यापिका अनुपात और अन्य कारकों के आधार पर मान्यता प्रदान करता है।

**5. भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई):** यह भारत की एक स्वायत्त व्यावसायिक विनियामक संस्था है, जो विधिक व्यवसाय और विधिक शिक्षा का नियमन करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी, जो भारत में अधिवक्ताओं के नियमन के लिए एक परिषद् के गठन का प्रावधान करती है। श्री मनन कुमार मिश्रा भारतीय विधिज्ञ परिषद् के वर्तमान अध्यक्ष हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद् का मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देती है और इसके मानक निर्धारित करती है, जो विश्वविद्यालयों और राज्य बार काउंसिल के परामर्श से किए जाते हैं, साथ ही ऐसे विश्वविद्यालयों को मान्यता देती है जो विधि में उपाधि प्रदान करते हैं, इसके लिए परिषद् विश्वविद्यालयों का दौरा और निरीक्षण करती है और राज्य बार परिषदों को निरीक्षण करने का निर्देश देती है, साथ ही विधिक विषयों पर सेमिनार और वार्ता आयोजित करती है और विधिक रुचि के जर्नल और शोधपत्र प्रकाशित करती है।

**6. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई):** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना वर्ष 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के तहत की गई थी। वर्तमान समय में एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा हैं। एनसीटीई का मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। यह भारत में अध्यापक शिक्षा को नियंत्रित करता है, संस्थाओं की मान्यता, पाठ्यक्रम ढाँचे का विकास और योग्यताओं एवं आधारभूत संरचना के मानकों के लिए दिशा-निर्देश तय करता है। एनसीटीई विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मापदंड और मानक निर्धारित करता है, जिससे अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित होती है।

**7. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी):** एनएमसी की स्थापना 25 सितम्बर 2020 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई, जिसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में एनएमसी के अध्यक्ष डॉ. बी. एन. गंगाधर हैं तथा इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। एनएमसी भारत में एक नियामक संस्था है जो चिकित्सा अभ्यास की निगरानी, नैतिक आचरण और पेशेवर मानकों को सुनिश्चित करता है। यह चिकित्सा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है तथा उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। यह चिकित्सा पेशेवरों को पंजीकरण करता है, जिससे उन्हें भारत में विधिक रूप से अभ्यास करने की अनुमति मिलती है।

**8. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर):** यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। पहले इसे 'इम्पीरियल

काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च' के नाम से जाना जाता था, जिसे 16 जुलाई 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक हैं तथा इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है। आईसीएआर के तहत राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड काम करता है, जो कृषि और संबंधित विज्ञानों के शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्रक्रिया संचालित करता है। यह बोर्ड विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता की जाँच करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों।

**9. भारतीय नर्सिंग परिषद् (आईएनसी):** भारतीय नर्सिंग परिषद् भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा संसद के भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3(1) के तहत किया गया था। वर्तमान समय में आईएनसी के अध्यक्ष टी. दिलीप कुमार हैं तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य नर्सिंग पेशे में उच्च मानकों को सुनिश्चित करना, नर्सिंग शिक्षा को विनियमित करना और योग्य नर्सिंग पेशेवरों को पंजीकरण प्रदान करना है। परिषद् नर्सिंग पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, निरीक्षण और मान्यता देती है और विभिन्न संस्थानों में नर्सिंग प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करती है। यह स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार और देश में नर्सिंग पेशे की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ये निकाय भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मापदंड निर्धारित करते हैं, जिससे शैक्षिक मानकों को बनाए रखा जा सके और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। नैक एक प्रमुख निकाय है, जो भारत में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता और मानक का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। यह संस्थानों के अकादमिक प्रदर्शन, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, विद्यार्थियों की सफलता, शोध कार्य और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे पहलुओं के आधार पर उनकी रेटिंग और मान्यता प्रदान करता है। नैक का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार करना और उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करना है। इसके माध्यम से संस्थानों को उनकी ताकत और सुधार की संभावनाओं का पता चलता है, जिससे वे अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर नैक द्वारा भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

### राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक)

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (नैक) एक स्वायत्त निकाय है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्य योजना, 1992 की संस्तुतियों के आधार पर 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित किया गया था (नैक, 2024)। नैक का आदर्श-वाक्य 'उत्कृष्टता, विश्वसनीयता और प्रासंगिकता' है। नैक का मुख्यालय कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु में स्थित है। इसका कार्यभार शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से होता है। वर्तमान में नैक के निदेशक प्रोफेसर गणेशन कन्नबीरन हैं। नैक का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों, उनके विभागों, विद्यालयों तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना और उन्हें प्रमाणित तथा प्रत्यायित करना है। नैक का

कार्य शैक्षिक प्रशासकों, नीति निर्माताओं और उच्च शिक्षा प्रणाली के वरिष्ठ शिक्षाविदों के एक समूह के माध्य से किया जाता है। 1 अप्रैल 2007 से नैक ने एक नयी दो-चरणीय पद्धति लागू की, जिसके तहत उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें प्रत्यायित किया जाता है। इस पद्धति में संस्थान के शैक्षिक मानकों, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक योगदान का आकलन किया जाता है ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार कर सकें (पाठक, 2023)। नैक के भारत में छह क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय बंगलुरु (मुख्य कार्यालय और दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय), नयी दिल्ली (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय), हैदराबाद (दक्षिण-मध्य क्षेत्रीय कार्यालय) तथा भोपाल (केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय) हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय नैक को विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शैक्षिक संस्थानों तक पहुँचने में मदद करते हैं, ताकि पूरे देश में प्रत्यायन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

दिनांक 21.08.2023 की रिपोर्ट के अनुसार नैक ने अब तक कुल 853 विश्वविद्यालय और 15890 महाविद्यालयों का मूल्यांकन कर प्रत्यायित किया है, जो भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है (नैक, 2023)।

### नैक की मूल्यांकन तथा प्रत्यायन प्रक्रिया

नैक ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर मूल्यांकन तथा प्रत्यायन के कई लाभ बताए हैं, प्रत्यायन के लाभ कई महत्वपूर्ण पहलुओं में संस्थानों को मदद प्रदान करते हैं। ये संस्थान को अपनी ताकत, सीमाओं और अवसरों को समझने का अवसर देते हैं, जिससे वे सुधार और विकास के लिए योजना बना सकते हैं। इसके माध्यम से संसाधनों के आवंटन और आंतरिक योजनाओं की पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यायन से संस्थान में सहकारिता बढ़ती है और संकाय सदस्यों के मध्य एक सकारात्मक वातावरण विकसित होता है। वित्तीय संस्थाएँ प्रदर्शन आधारित अनुदान के लिए उद्देश्यपूर्ण प्रदत्तों की तलाश करती हैं और प्रत्यायन से संस्थान को नवीन और आधुनिक शिक्षण विधियों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। यह संस्थानों को एक नयी दिशा और पहचान प्रदान करता है, जिससे उनका समग्र विकास होता है। समाज, रोजगार का अवसर प्रदान करने वाले अभिकरण और भविष्य में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह विश्वसनीय जानकारी का स्रोत बनता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। अंततः, प्रत्यायन संस्थानों के मध्य अंतर-संस्थागत और अंतरसंस्थागत संवाद को बढ़ावा देता है जो सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित करता है (गौतम, 2024)।

नैक की मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया उच्च शिक्षा संस्थानों की शैक्षिक गुणवत्ता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की एक सुव्यवस्थित और व्यापक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित सात सोपानों में पूरी होती है—

### प्रथम सोपान : संस्थागत पंजीकरण और आईआईक्यूए की प्रस्तुति

संस्थान को नैक से मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले नैक के आधिकारिक पोर्टल पर संस्थागत पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी



होने के बाद, इंस्टीट्यूशनल इन्फार्मेशन फॉर क्वालिटी असेसमेंट (गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु संस्थागत सूचना) को आईआईक्यूए फॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करना होता है। आईआईक्यूए में संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जिसमें संस्थान का शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक उपलब्धियाँ, पाठ्यक्रम और पाठ्यसहगामी गतिविधियाँ, शैक्षिक प्रदर्शन, शोध एवं विकास, विद्यार्थी सहायता सेवाएँ और विशेष रूप से गुणवत्ता सुधार के लिए किए गए प्रयासों का विवरण शामिल होता है। यह जानकारी नैक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तत्पर है। आईआईक्यूए की प्रस्तुति के बाद नैक इस जानकारी का गहन मूल्यांकन करता है। यदि संस्थान द्वारा दी गई जानकारी और प्रलेख मानदंडों और मानकों के अनुरूप होते हैं तो उसे मूल्यांकन और प्रत्यायन की प्रक्रिया के अगले सोपान में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया संस्थान की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संस्थानों को पंजीकरण करने के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होती है। पात्रता सुनिश्चित करने के लिए दो योग्यताओं में से एक का होना अनिवार्य है। उच्च शिक्षा संस्थान जिनके पास कम से कम स्नातक स्तर के दो बैच पूर्ण हो चुके हों या जिनकी स्थापना को छह वर्ष हो चुके हों, वे नैक के मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए आवेदन करने के योग्य होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नैक का प्रत्यायन दूरस्थ शिक्षा इकाइयों और विदेशी परिसरों को सम्मिलित नहीं करता है। सभी संस्थानों को नैक द्वारा मूल्यांकन और प्रत्यायन के लिए आवेदन करने से पहले अनिवार्य रूप से अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड करनी होती है, और एआईएसएचई कोड (संदर्भ संख्या) पंजीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त है।

### द्वितीय सोपान : स्व-अध्ययन रिपोर्ट

नैक द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए स्व-अध्ययन रिपोर्ट (एसएसआर) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसमें संस्थान की शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्य गतिविधियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। स्व-अध्ययन रिपोर्ट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में गुणात्मक और मात्रात्मक दो प्रकार के मापदंड होते हैं जो संस्थान की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करते हैं। गुणात्मक मापदंड में संस्थान की कार्यप्रणाली, प्रशासन, अपनाई जाने वाली नीतियाँ, उपागम, शैक्षिक गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता, अध्यापकों की विशेषज्ञता और विद्यार्थियों की संलग्नता आदि विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी होती है। मात्रात्मक मापदंड में मापने योग्य तथा प्रदत्त आधारित जानकारी जैसे संकाय सदस्यों की संख्या, विद्यार्थी नामांकन, परीक्षा परिणाम, शोध कार्य तथा प्रकाशन आदि प्रस्तुत किया जाता है।

ये मापदंड नैक की ग्रेडिंग और मूल्यांकन में सहायक होते हैं और संस्थान को आगे की प्रक्रिया के लिए आमंत्रित करने के लिए इनका सही ढंग से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। नैक के मूल्यांकन में एक सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी-आधारित प्राप्तांकों का उपयोग किया जाता

है, जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों मापदंडों को मिलाकर संस्थान की गुणवत्ता को दर्शाता है। इसके साथ, सहकर्मी टीम रिपोर्ट, मात्रात्मक संकेतकों का रेखा-चित्रिय प्रदर्शन और संस्थागत ग्रेड शीट प्रदान की जाती है, जिससे संस्थान की शैक्षिक गुणवत्ता और विकास के प्रयासों का समग्र मूल्यांकन होता है।

### तृतीय सोपान : मापदंड आधारित मूल्यांकन

नैक की मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया का मुख्य स्तम्भ 'मापदंड-आधारित मूल्यांकन' है। इसमें कुल सात मापदंड सम्मिलित किए गए हैं। यह सात मापदंड उच्च शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली और गतिविधियों के मुख्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संशोधित रूपरेखा में न केवल संस्थान के शैक्षिक और प्रशासनिक पहलुओं को शामिल किया गया है, बल्कि उभरते हुए मुद्दों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक व्यापक और प्रासंगिक बन सके (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2024)।

### मापदंड 1 : पाठ्यक्रम पहलू

पाठ्यक्रम किसी भी शैक्षिक संस्थान का मूल स्तम्भ होता है, लेकिन विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों की इस संदर्भ में जिम्मेदारियाँ उनके प्रशासनिक ढाँचे के आधार पर भिन्न होती हैं। एक संबद्ध महाविद्यालय मुख्य रूप से शिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करता है और इसके शैक्षिक व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मान्यता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय पर निर्भर होता है। इसका योगदान पाठ्यक्रम के विकास में सीमित रहता है और यह मुख्यतः पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने तक ही सीमित होता है। विश्वविद्यालय को विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने, उसे समय-समय पर अद्यतन करने और इसके परिणामों की परिभाषित करने का अधिकार होता है, जबकि संबद्ध महाविद्यालयों को इन निर्णयों में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। स्वायत्त महाविद्यालयों की जिम्मेदारियाँ विश्वविद्यालयों के समान होती हैं, जिससे वे पाठ्यक्रम के विकास, अद्यतन और मूल्यांकन में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। मापदंड 1 का उद्देश्य ऐसे कार्यक्रम और पाठ्यक्रम विकसित करना है, जो राष्ट्रीय व वैश्विक प्रवृत्तियों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इसमें पाठ्यक्रम में लचीलापन, रोजगार उन्मुखीकरण, बहु-कौशल विकास और प्रतिक्रिया प्रणाली जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। इसके प्रमुख संकेतक पाठ्यक्रम अभिकल्प और योजना, शैक्षिक लचीलापन, पाठ्यक्रम संवर्धन और प्रतिक्रिया प्रणाली हैं।

### मापदंड 2 अध्यापन : अध्ययन एवं मूल्यांकन

यह मापदंड संस्थानों द्वारा विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षमताओं के विद्यार्थियों को प्रभावी और समावेशी शिक्षण-अधिगम अनुभव प्रदान करने के प्रयासों का मूल्यांकन करता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता और व्यावहारिक कौशल विकसित करना है। शिक्षण विधियों में साक्षात्कार, वाद-विवाद, परियोजनाएँ, प्रयोग, इंटर्नशिप और आईसीटी संसाधनों का उपयोग शामिल है। साथ ही, यह अध्यापकों की योग्यता, व्यावसायिक विकास, और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का आकलन करता है। इस मापदंड के तहत सात प्रमुख संकेतकों अर्थात् विद्यार्थी नामांकन, विविधता, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, अध्यापक प्रोफाइल, मूल्यांकन सुधार,

विद्यार्थियों का प्रदर्शन और संतोष सर्वेक्षण का विश्लेषण किया जाता है। यह मापदंड विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अध्यापकों के विकास और संस्थान की समग्र शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

### मापदंड 3 : अनुसंधान, नवाचार और विस्तार

मापदंड 3 संस्थान की उन नीति, उपागम और परिणामों का आकलन करता है, जो शोध, नवाचार और विस्तार गतिविधियों से संबंधित हैं। यह संस्थान द्वारा शोध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल और प्रदान की गई सुविधाओं पर केन्द्रित है। संस्थान का दायित्व है कि वह संकाय सदस्यों को समाज के लिए उपयोगी शोध कार्य करने में सक्षम बनाए और समुदाय की सेवा करने जैसी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करे। इस मापदंड के अंतर्गत शोध को प्रोत्साहित करने, संसाधनों का संग्रहण, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास, शोध प्रकाशनों और पुरस्कारों को बढ़ावा देने, परामर्श सेवाओं की पेशकश, समाज के साथ जुड़ाव के लिए विस्तार गतिविधियों का संचालन और सहयोगात्मक पहलों को प्रोत्साहित करने का मूल्यांकन किया जाता है। यह मापदंड संस्थान की शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की क्षमता और समाज के प्रति उसके योगदान का मापन करता है।

### मापदंड 4 : आधारभूत सुविधाएँ एवं अध्ययन संसाधन

संस्थान की उपलब्ध सुविधाओं की पर्याप्तता और उनका उचित उपयोग शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस मापदंड के तहत संस्थान के विद्यार्थी, अध्यापक और कर्मचारियों द्वारा इन सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें भौतिक सुविधाओं, पुस्तकालय की सेवाओं, आईटी संरचना और परिसर की संरचना के रखरखाव की समीक्षा की जाती है। इसके साथ ही, संस्थान के भविष्य के विकास के लिए सुविधाओं का विस्तार और उन्नति पर भी ध्यान दिया जाता है। इन सभी पहलुओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि संस्थान उच्च शैक्षिक मानकों को बनाए रखते हुए अपनी संरचनात्मक और संसाधन जरूरतों को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर रहा है।

### मापदंड 5 : विद्यार्थी सहायता एवं प्रगति

मापदंड पाँच का मुख्य उद्देश्य यह है कि संस्थान विद्यार्थियों को आवश्यक सहायता प्रदान करे, ताकि वे परिसर में शैक्षिक अनुभवों को प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें और उनका समग्र विकास एवं उन्नति सुनिश्चित हो सके। यह मापदंड विद्यार्थियों के प्रदर्शन, पूर्व विद्यार्थियों के प्रोफाइल और विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में प्रगति, साथ ही रोजगार प्राप्ति की दिशा में उनके कदमों पर भी ध्यान देता है। इसमें विद्यार्थी सहायता, उनकी प्रगति, गतिविधियों में भागीदारी और पूर्व विद्यार्थियों के साथ संबंधों के प्रबंधन जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक और कैरियर संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समग्र समर्थन प्रणाली मिल रही है।

## मापदंड 6 : प्रशासन, नेतृत्व और प्रबंधन

संस्थान के प्रभावी संचालन का मूल्यांकन उसकी नीति और उपागमों के आधार पर किया जा सकता है, जो मानव संसाधन की योजना, भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन मूल्यांकन, वित्तीय प्रबंधन और नेतृत्व की भूमिका से संबंधित हैं। मापदंड 6 का मुख्य उद्देश्य इन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना है, जो संस्थान की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए विकसित किए गए हैं। इस मापदंड में संस्थान का दृष्टिकोण और नेतृत्व, रणनीति विकास और कार्यान्वयन, संकाय सशक्तीकरण युक्तियाँ, वित्तीय प्रबंधन और संसाधन संकेंद्रण तथा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली जैसे प्रमुख संकेतक शामिल किए गये हैं। इन संकेतकों के माध्यम से संस्थान के शासन, नेतृत्व और प्रबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है।

## मापदंड 7 : संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएँ

एक शैक्षिक संस्थान देश की शिक्षा प्रणाली में कार्य करते हुए उभरती चुनौतियों और मुद्दों के प्रति संवेदनशील होता है। उसे सामाजिक जिम्मेदारी के तहत विकास में सक्रिय प्रयास करना होता है, जो उसके कार्यक्रम, गतिविधि और मूल्यों के माध्यम से परिलक्षित होता है। संस्थान की प्रभावशीलता उसके द्वारा उठाए गए कदमों और उनके परिणामों से स्पष्ट होती है। हर संस्थान को लिंग समानता, पर्यावरण चेतना, समावेशन और पेशेवर नैतिकता जैसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और इन्हें हल करने के विशिष्ट तरीके विकसित होते हैं। समय के साथ संस्थान अपनी विशिष्ट कार्यप्रणाली के कारण एक पहचान विकसित करता है। मापदंड सात में संस्थान के मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियाँ, श्रेष्ठ अभ्यास तथा संस्थान की विशिष्टता जैसे प्रमुख संकेतक सम्मिलित किए गए हैं।

## चतुर्थ सोपान : आँकड़ों का सत्यापन और पुष्टि

नैक में आँकड़ों का सत्यापन और पुष्टि एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए गए आँकड़ों की सटीकता, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। आँकड़ों के सत्यापन के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रस्तुत जानकारी प्रारूप के अनुसार सही, पूर्ण और संगत हो, जबकि आँकड़ों की पुष्टि में उसकी विश्वसनीयता की जाँच की जाती है। नैक अपने डाटा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन (डीवीवी) प्रक्रिया के तहत आईसीटी आधारित उपकरण, तृतीय पक्ष समीक्षा और सहकर्मियों टीम के दौरे के माध्यम से प्रदत्तों का मूल्यांकन करता है। इसके लिए संस्थान के दस्तावेज़, रिपोर्ट और सार्वजनिक स्रोतों से जानकारी का मिलान किया जाता है। संस्थानों को अपने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के माध्यम से आँकड़ों की तैयारी और सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। यह प्रक्रिया संस्थानों को पारदर्शिता बनाए रखने और बेहतर प्रत्यायन परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है।

## पाँचवा सोपान : सहकर्मियों टीम का दौरा

नैक की सहकर्मियों टीम का गठन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एकत्रित किया जाता है ताकि वे संस्थान की गुणवत्ता का सटीक तथा उत्तम मूल्यांकन कर सकें। टीम में शैक्षिक, प्रशासनिक, शोध, आधारभूत संरचना, विद्यार्थी कल्याण और वित्तीय प्रबंधन

जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। चयनित टीम को नैक एक आधिकारिक पत्र भेजता है, जिसमें उनकी जिम्मेदारियों और यात्रा की जानकारी दी जाती है। दौरे से पहले, टीम संस्थान की स्व-आकलन रिपोर्ट और अन्य आवश्यक जानकारी पढ़कर संस्थान को समझती है और फिर मूल्यांकन के लिए योजना बनाती है।

सहकर्मी टीम का ऑन-साइट मूल्यांकन संस्थान का प्रत्यक्ष निरीक्षण होता है, जिसमें टीम शैक्षिक गुणवत्ता, संसाधन, अवसंरचना, शोध कार्य, विद्यार्थी कल्याण सेवाएँ और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करती है। यह सुनिश्चित करती है कि संस्थान की सुविधाएँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के लिए उपयुक्त हैं। टीम पाठ्यक्रम, शोध और अन्य कार्यक्रमों का मूल्यांकन करती है और विद्यार्थी, अभिभावक और हितधारकों से प्रतिक्रिया लेती है।

सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सहकर्मी टीम संस्थान द्वारा दी गई जानकारी, आँकड़ें और रिपोर्ट्स की गहराई से जाँच करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी दावे और आँकड़े सही और वास्तविक हैं। टीम स्व-आकलन रिपोर्ट में दी गयी जानकारी (शैक्षिक, प्रशासनिक और वित्तीय डेटा) की समीक्षा करती है और संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त करती है। वे संस्थान द्वारा दिए गए आँकड़ों को उनके वास्तविक संदर्भ से सत्यापित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि संस्थान की सभी व्यवस्थाएँ पारदर्शी और सटीक हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संस्थान के गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता का सही मूल्यांकन करना है, ताकि नैक का मूल्यांकन निष्पक्ष और सटीक हो।

एग्जिट मीटिंग का आयोजन मूल्यांकन के बाद होता है, जिसमें सहकर्मी टीम संस्थान के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी टिप्पणियाँ और निष्कर्ष साझा करती है। इसमें संस्थान की गुण, सीमाएँ और सुधार के लिए सुझाव दिए जाते हैं, जिससे संस्थान को अपने कार्यों और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन मिलता है।

### छठा सोपान : ग्रेडिंग तथा प्रत्यायन

नैक द्वारा संस्थानों के मूल्यांकन के पश्चात् एक संस्थागत ग्रेड शीट तैयार की जाती है, जो संस्थान की शैक्षिक और प्रशासनिक गुणवत्ता का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। यह ग्रेड शीट गुणवत्ता संकेतकों, मात्रात्मक संकेतकों और विद्यार्थी संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर बनाई जाती है और इसके निर्माण के लिए मौजूदा गणना विधियों का उपयोग किया जाता है। यह ग्रेड शीट सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित की जाती है, जिससे संस्थान के सभी संबंधित आँकड़ों का सही तरीके से मूल्यांकन और प्रसंस्करण होता है। संस्थान को यह रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है, ताकि यह विद्यार्थी और अन्य हितधारकों को उपलब्ध हो सके। नैक इसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करता है।

संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) के आधार पर संस्थान को एक ग्रेड दिया जाता है, जो उसकी समग्र गुणवत्ता को दर्शाता है। यदि संस्थान का सीजीपीए 3.51 से 4.00 के मध्य है, तो उसे **A++** (प्रत्यायित) दर्जा प्राप्त होता है, और यदि सीजीपीए 1.50 से कम है, तो संस्थान को **D** (अप्रत्यायित) के रूप में मूल्यांकित किया जाता है।

संस्थागत संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए)	अक्षर	स्थिति
3.51 – 4.00	A++	प्रत्यायित
3.26 – 3.50	A+	प्रत्यायित
3.01 – 3.25	A	प्रत्यायित
2.76 – 3.00	B++	प्रत्यायित
2.51 – 2.75	B+	प्रत्यायित
2.01 – 2.50	B	प्रत्यायित
1.51 – 2.00	C	प्रत्यायित
≤ 1.50	D	प्रत्यायित नहीं

उदाहरण के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) के 3.55 सीजीपीए के साथ A++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। यह ग्रेड विश्वविद्यालय को पहली बार वर्ष 2022 में मिला, जबकि इससे पहले 2020 में इसे B ग्रेड प्राप्त हुआ था (इयांस तथा इयांस, 2022)। इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 2018 में 3.28 सीजीपीए के साथ A+ ग्रेड प्राप्त हुआ (डीयू, नैक रिपोर्ट, 2023)।

### सातवाँ सोपान : मान्यता के बाद की प्रक्रिया

नैक से मान्यता प्राप्त करने के बाद, संस्थान को अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करने होते हैं। इस प्रक्रिया में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो संस्थान के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखता है। आईक्यूएसी द्वारा प्रत्येक वर्ष 'वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट' (एक्यूएआर) तैयार की जाती है, जिसमें संस्थान द्वारा किए गए सुधार, योजनाएँ और प्राप्त परिणामों का विवरण होता है। एक्यूएआर में उन गतिविधियों का उल्लेख होता है जो संस्थान ने मान्यता के दौरान निर्धारित किए गए मानक और लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यह रिपोर्ट नैक को भेजी जाती है और इसे संस्थान की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रक्रिया से संस्थान की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है और उसे अगले मूल्यांकन के लिए तैयार किया जाता है।

## उपसंहार

नैक की मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया उच्च शिक्षा संस्थानों के शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्य कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित और सटीक तरीका है। यह प्रक्रिया संस्थान को उनकी गुण, सीमाओं और सुधार के क्षेत्रों को पहचानने में मदद करती है, जिससे वे भविष्य में अपनी गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। इसके माध्यम से संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करते हैं, जो उनके समग्र विकास के लिए सहायक होता है। नैक द्वारा निर्धारित मापदंड और श्रेणियाँ संस्थानों को शिक्षा की गुणवत्ता को निरंतर सुधारने और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करती हैं, साथ ही, यह प्रक्रिया संस्थानों के मध्य संवाद और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलता है।

## सन्दर्भ

1. डीयू नैक रिपोर्ट-2023. <https://www.du.ac.in/uploads/-30112018Press-Release---Delhi-University-NAAC-Grading.jpg>
2. इयांस तथा इयांस. (2022). लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट्स ए++ ग्रेड बाई नैक. द स्टेट्समैन <https://www.thestatesman.com/india/lucknow-university-gets-grade-naac-1503093885.html>
3. गौतम, ए. एस. (2024). इम्पैक्ट ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (नैक) ऑन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (एचईआईएस) इन इंडिया. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथोड्स*, 12(8) 1530–1541. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4932646>
4. गुप्ता, ए. (2021). फोकस ऑन क्वालिटी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया. *इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन*, 67(1), 54–70. <https://doi.org/00195561211007224/10.1177>
5. होता, पी. एवं सारंगी, पी. (2021). क्वालिटी रेवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशनरू ए स्टडी इन इंडिया. *सृष्टी मैनेजमेंट रिव्यू*, 12(1). 49–56.
6. मेहर, वी. तथा बराल, आर. (2018). क्वालिटी अस्योरेंस इन हायर एजुकेशन-नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (नैक). *इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज*, 4(11). 1–6.
7. नैक. (2024). नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल (नैक). <https://naac.gov.in>
8. नैक. (2023). टोटल नंबर ऑफ एक्रेडिएशंस (स्टेटस एस ऑन 21-08-2023). <http://naac.gov.in/images/docs/STATISTICS/Total Number of Accreditations Status as on -21 2023-08 .2023-08-28pdf>
9. नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल (नैक). <http://naac.gov.in/index.php/en/about-us>
10. पाठक, पी. (2023). रोल ऑफ नैक इन इम्प्रोविंग क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. *इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स*, 11(3). 133–134.
11. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार. (2024). नैक प्रोसेस. <https://www.education.gov.in>
12. वर्थना. (2023). लिस्ट ऑफ हायर एजुकेशन एक्रेडिएशन्स बॉडीज ऑफ इंडिया 2024. <https://varthana.com/student/list-of-higher-education-accreditations-bodies-of-india-/2023>

# *Journal*